मेरी खेती

PAGE NO. 1-33, MARCH 2023

किसान समाचार

खेत खलियान
सरकारी नीतियां
मौसम व अन्य कृषि सुझाव
सब्ज़ी
फूल
औषधीय खेती
पशुपालन - पशुचारा
प्रगतिशील किसान

MERI KHETI

द्रोपदी मुर्मू के द्वारा स्वीकृत किए गए इस विधेयक से 11 हजार काश्तकारों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम कृषि सुधार से जुड़ा कदम है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को काफी प्रोत्साहन मिलेगा एवं पैदावार भी बढ़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पंजाब के एक विधेयक को स्वीकृति प्रदान करदी गई है। मंजूरी मिलते ही यह विधेयक फिलहाल कानून में परिवर्तित हो गया है। इस कानून के चलते प्रदेश के 4,000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर कब्जा रखने वाले 11,200 से भी अधिक काश्तकारों को मालिकाना हक मिल पाएगा। एक अधिकारी का कहना है, कि सरकार को आशा है, कि यह कानून भूमि जोतने वालों को मजबूत करेगा। साथ ही, जो लोग समाज में आर्थिक एवं सामाजिक तौर से लाचार, उन्हें भी सशक्त बनाएगा।

जानकारी के अनुसार, यह काश्तकार बहुत सालों से जमीन के छोटे-छोटे हिस्सों पर काबिज हैं।साथ ही, पीढ़ी-दर-पीढ़ी उत्तराधिकारी के तौर पर स्वयं का अधिकार प्राप्त करते हैं। चूंकि, वह पंजीकृत स्वामी नहीं थे, इसलिए ना तो वह वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकते थे। साथ ही, किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें सहायता मिलती थी। लेकिन अब उन्हें अन्य भूस्वामियों की तरह सभी लाभ मिलेंगे।

कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता में वृद्धि होगी

इस विधेयक से समुचित सहायक धनराशि का भुगतान करने के उपरांत 4,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा रखने वाले 11,200 से ज्यादा काश्तकारों को संपत्ति के अधिकार की अनुमति देता है। साथ ही, एक आधिकारिक बयान में बताया गया है, कि यह अधिनियम कृषि सुधार से संबंधित कदम है। वहीं, इससे कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा एवं पैदावार भी बढ़ेगी।

-दिलीप यादव

खेत खलियान

गेहूं चना और आलू की खेती करने वाले किसान कैसे बचा सकते हैं अपनी फसल

मौसम की अनिश्चितताओं के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मौसम के बदलते मिज़ाज को देखते हुए खेती से जुड़ी एक एडवायजरी जारी की है। ताकि इस बार सही समय पर सही कदम उठाते हुए फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है, कि अगर उनके इलाके में ज्यादा बारिश हुई है तो अपनी खड़ी फसल में अब वे सिंचाई ना करें।

कैसे कर सकते हैं किसान गेहूं की फसल की निगरानी

इस मौसम में गेहूं की फसलों में रतुआ रोग काफी ज्यादा देखने को मिलता है। माना जा रहा है, कि अगर इस रोग पर पहले से ध्यान दिया जाए तो फसल को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। अगर गेहूं की फसल में पत्तियों पर आपको काले, पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो तुरंत डाइथेन एम-45 की 2.5 ग्राम मात्रा एक लीटर पानी में मिलाकर पूरी फसल पर छिडकाव करें। ऐसा करने से फसल को इस रोग से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

पीला रतुआ रोग गेहूं में 10-20°C तापमान के बीच होता है। अगर तापमान 25 डिग्री से ऊपर चला जाए तो रोग गेहूं को प्रभावित नहीं करता है। इसी तरह से भूरा रतुआ रोग 15-25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। साथ ही, भूमि में नमी हो तो ये और फैल जाता है।

चने की फसल में कैसे करें कीट से बचाव

चने की फसल को छेदक कीट लगने का खतरा बन रहता है। अगर फसल में फुल आ गए हैं तो 3 से 4 फैरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने पर इससे बचा जा सकता है।

आलू की फसल का बचाव कैसे करें

अगर आपने आलू की खेती की है तो इसमें झुलसा रोग होने की संभावना रहती है। एक बार इस रोग के लक्षण देखते ही 2 ग्राम कैप्टान एक लीटर पानी में मिलाकर पूरी फसल पर छिडकाव करें।

मालाबार नीम की खेती करते हुए किसान कमा रहे हैं, लाखों का मुनाफा, जाने कैसे ले सकते हैं सब्सिडी

पिछले कुछ सालों में भारत में खेती के स्वरूप में काफी बदलाव आए हैं और आजकल हर जगह मल्टीटास्किंग खेती की बात हो रही है। फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और पेड़ की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

अंतरवर्तीय और मिश्रित खेती को भी खासतौर पर बढ़ावा मिल रहा है, जिससे किसानों को कम समय में अच्छी आमदनी हो जाती है।

जब भी किसान मल्टीटास्किंग खेती करता है, तो उसके उत्पादन की लागत कम हो जाती है और एक ही खाद बीज और कीटनाशक का इस्तेमाल करते हुए कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। आज दुनियाभर के किसान इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। भारतीय किसानों को भी इस मॉडल से जुड़ने के लिए सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद दे रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाई है, जिसके तहत पेड़ों की व्यवसाय खेती करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

मालाबार नीम की खेती

मालाबार नीम की लकड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है, कि उस में दीमक लगने की संभावना नहीं होती है। यही कारण है, कि देश और दुनिया में फर्नीचर की मार्केट में इस लकड़ी की बहुत ज्यादा डिमांड है। किसान अपने पूरे खेत में नीम की खेती नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में वह खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर मालाबार नीम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ ही साल में पौधे बड़े होने के बाद उन्हें बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।

किस काम आती है मालाबार नीम की लकड़ी

आपको बता दें मालाबार नीम की लकड़ी का इस्तेमाल कृषि उपकरण, भवन निर्माण, पेंसिल, माचिस की डिब्बी, संगीत वाद्ययंत्र, चाय की पेटी, फलों की पेटी, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग, चौकी जैसे फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है।
मालाबार नीम का पेड़ कुछ ही सालों में लगभग 7 से 8 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि इसकी खेती में बहुत ज्यादा खाद और रसायनों का खर्चा नहीं आता है।

यह राशि किसानों को तीन टेस्ट में दी जाएगी। पहले साल में पहली किश्त के तौर पर 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। दूसरे साल और तीसरे साल में क्रमशः साथ 7,000 की आर्थिक मदद किसानों को दी जानी है।
इस तरीके से कुल मिलाकर 25,500 रुपये की अनुदान राशि किसानों को दी जा रही है।
आवेदन देने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- किसान का आधार कार्ड
- किसान का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- किसान का आय प्रमाण पत्र
- किसान के बैंक पासबुक की कॉपी
- जमीन के कागजात (खसरा खतौनी की कॉपी)
- किसान का मोबाइल नंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

कहां कर सकते हैं आवेदन

अगर आप अपने खेत में मालाबार नीम की खेती करना चाहते हैं। तो इसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा। यहां जाकर किसान अपने जरूरी दस्तावेज अटैच करते हुए अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद वन विभाग के कार्यालय में अच्छी तरह से रिव्यु करने के बाद सबमिट कर दिया जाता है। उचित आवेदन होने पर राशि का आवंटन किया जाता है।

सब्ज़ी

मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए यह राज्य दे रहा है 40% तक सब्सिडी

आजकल भारत में अंतरवर्तीय खेती बहुत ज्यादा चलन में है। पारंपरिक फसलों के साथ-साथ किसान सब्जी, फल, औषधि और मसालों की भी खेती करने लगे हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी तो मिल ही जाती है। पिछले कुछ समय से मशरूम भी एक ऐसी ही फसल है जो प्रमुख बागवानी फसल बनकर सामने आई है। बिहार जैसे कई राज्य मशरूम की खेती करते हुए अच्छा-खासा मुनाफा कमा रहे हैं। दूसरे राज्य भी आज बिहार से प्रेरित होकर मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देश-विदेश में सुपरफूड के तौर पर इस फंगी/कवक की मांग बढ़ रही है।

बिहार की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार भी मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है। राज्य में किसानों को मशरूम यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार ने किसानों से इसके लिए आवेदन भी मांगे हैं।

कैसे ले सकते हैं अनुदान का लाभ

मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के लिए राजस्थान की सरकार 40% सब्सिडी पर 8 लाख रुपये का क्रेडिट लिंक बैक एंडेड अनुदान देती है। अगर आप 2000000 रुपए तक की लागत में मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके लिए 40% की सब्सिडी सरकार द्वारा आप को दी जाएगी। इसके लिए सरकार 8 लाख रुपये प्रति इकाई क्रेडिट लिंक बैक एंडिडयड अनुदान देती है।

वहीं 15 लाख रुपये तक की लागत वाली इकाई के लिए भी 40% अनुदान पर 6 लाख रुपये का क्रेडिट लिंक बैक एंडिड अनुदान दिया जाता है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ

मशरूम एक बागवानी फसल है और इसी के तहत राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इसके लिए अनुदान दे रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अनुदान देने के लिए कुछ जिले चयनित किए हैं। जो इस प्रकार से हैं।

अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बांरा और करौली के किसान या किसानों के समूह को ही अनुदान के लिए शामिल किया गया है।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

अगर आप भी राजस्थान से हैं और मशरूम उत्पादन यूनिट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सरकार की तरफ से दी जा रही क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी योजना का लाभ आप ले सकते हैं।

इस स्कीम में आवेदन करने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहां पर कार्यालय में जाकर ही आप इस योजना से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं। जानकारी के बाद कृषि विभाग में ही आप ऑफलाइन अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं या फिर किसी नजदीकी मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर भी निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि किसानों को आवेदन के साथ कुछ डोक्यूमेंट भी अटैच करने होंगे। जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, किसान का शपथ पत्र या लोन की कॉपी, जनाधार या भामाशाह कार्ड की कॉपी और अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सब्मिट करनी होगी।

गेहूं पर गर्मी पड़ सकती है भारी, उत्पादन पर पड़ेगा असर

इस बार देश में गेहूं की बुवाई रिकार्ड क्षेत्र में की गयी है. रिकॉर्ड बुवाई को देखते हुए इस बार 11 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं के उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन इस बार बढ़ती गर्मी गेहूं पर भारी पड़ सकती है. जिसका सीधा असर इसके उत्पादन पर दिख सकता है.

साल 2022 की गर्मी का सितम कौन भूल सकता है. जिसने सबसे ज्यादा गेहूं की फसल पर सितम बरपाया था. हालंकि इस साल किसान उस मुश्किल से उबरने की सोच ही रहे थे कि, इस साल गेहूं में बंपर उत्पादन होगा. लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. इस साल की बढ़ती गर्मी गेहूं की फसल को बर्बाद कर सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी में होता है. जहां फरवरी का पहला हफ्ता बेहद गर्म गया है. अगर ऐसे ही हालात रहें तो, इसका सबसे ज्यादा असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है.

वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो अगर गर्मी का सितम वहां पर भी बरकरार रहा तो, वहां के गेहूं के उत्पादन की स्थिति बिगड़ सकती है.

एक्टिव मोड पर आई केंद्र सरकार
पिछले साल गेहूं का उत्पादन गर्मी की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था. वहीं इस साल आधे फरवरी में ही टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है. जिस वजह से गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने में प्रभावित होने का अंदेशा है. जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक निगरानी कमेटी का गठन किया है. जो गेहूं की फसल को क्या नुकसान होगा, का आंकलन करेगी. कृष्ण आयुक्त को कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है I

एक्टिव मोड पर आई केंद्र सरकार

पिछले साल गेहूं का उत्पादन गर्मी की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था. वहीं इस साल आधे फरवरी में ही टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है. जिस वजह से गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने में प्रभावित होने का अंदेशा है. जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक निगरानी कमेटी का गठन किया है. जो गेहूं की फसल को क्या नुकसान होगा, का आंकलन करेगी. कृष्ण आयुक्त को कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है

इन राज्यों को सबसे ज्यादा खतरा

मौसम विभाग की मानें तो गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां का तापमान समान्य से ज्यादा हो सकता है. मतलब साफ़ है कि, तापमान में बढ़ोतरी के जद सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि कई राज्य हैं. इन सभी राज्यों के गेहूं की फसल की निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है.

वहीं अधिकारीयों की मानें तो, जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, उसे देखते हुए कृषि मंत्रालय की कमेटी किसानों को कम सिंचाई से जुड़ी जरूरी जानकारी देगी. जिसकी अध्यक्षता कृषि आयुक्त डॉक्टर प्रवीन करेंगे. इसके अलावा कमेटी का अन्य सदस्य में गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे I

अधिकारीयों का कहना है कि, इस साल देश में गेहूं की बुवाई रिकॉर्ड क्षेत्रों में की गयी है. वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक तापमान ज्यादा होने का असर जमीन में दिखेगा. यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि, तापमान में हुए बदलाव की वजह से जनवरी का महीना सबसे ज्यादा ठंडा और गर्मी का महीना सबसे ज्यादा गर्म है. जिसका असर फसलों पर देखने को मिल सकता है I

बात जुलाई से जून तक की साल 2022 से 2023 की करें तो, इस साल गेहूं की पैदावार 11 करोड़ टन से भी ज्यादा होने का अंदेशा जताया जा रहा है. क्योंकि देश में इस साल पिछले साल की तुलना में गेहूं का रकबा बढ़ा है. वहीं पिछले साल लू की वजह से गेहूं की उत्पादकता में कमी आई थी. जहां गेहूं का उत्पादन बेहद कम रहा गया था.

फल

करनी है बंपर कमाई, तो बनिये बागवानी मिशन का हिस्सा

किसानों की अच्छी आय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काफी मेहनत कर रही है. इसके लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार धरातल में उतार रही है. जिसके लिए सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है. ताकि उनकी आर्थिक रूप से मदद हो सके I

सरकार की तरफ से किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा किसानों को बागवानी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. हालांकि बागवानी की खेती करके किसानों को सब्सिडी भी दी जाती है. ताकि किसानों की आर्थिक मदद हो सके. बागवानी की खेती करके किसानों की अच्छी कमाई हो रही है. छत्तीसगढ़ में किसान बागवानी के जरिये अमरूद, केला, आंवला और आम जैसे फलों की खेती कर रहे हैं I

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तर्ज पर राज्य सरकार कृषि के साथ साथ उद्यानिकी फसलों से जुड़े क्षेत्रों के विस्तार और उत्पादन में बढ़ोतरी करना चाहती है. बता दें इस योजना के तहत राज्य के मुंगेली जिले के अंतर्गत करीब 443 सदस्य कृषकों की तीन ने समेती लाभंडी रायपुर में प्रशिक्षण लिया है. यह प्रशिक्षण 1 फरवरी, 2 से 4 फरवरी, 6 से 8 फरवरी, 9 से 11 फरवरी, 20 से 22 फरवरी और 23 से 25 फरवरी 2023 तक चला. आपको बता दें कि, इस दौरान किसानों ने नई तकनीक से कैसे खेती करनी है, इसका गुण भी सीखा I

इस तरह मिली जानकारी

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले के किसानों ने उद्यानिकी फसलों से जुड़ी दाल और सब्जियों जैसी उन्नत तकनीक से खेती करने की जानकारी शामिल है. इसके तहत कीट प्रबंधन, बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी जानकारी, बीजों का उत्पादन, फूलों के उत्पादन तकनीक से जुड़ी सम्भावनाएं, मशरूम का उत्पादन की खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की भी जानकारी दी गयी I

इंदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय के साइंटिस के अलावा विषय वस्तु से जुड़े एक्सपर्ट्स और संस्थान के अधिकारीयों ने इन सभी विषयों में टेक्निकल जानकारी किसानों को दी. यह प्रशिक्षण 14 महिलाओं और 55 पुरुषों ने 23 से 25 फरवरी के भ्रमण दौरे के दौरान लिया. इस दौरान दौरे पर आये हुए किसानों ने राज्य सरकार की इस नई तकनीक की काफी ज्यादा सरहाना की. साथ ही इस तकनीक को अपनाने की बात भी कही. इसके अलावा राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान ने किसानों को सर्टिफिकेट बांटा I

किसान कर लें ये काम, वरना पपीते की खेती हो जाएगी बर्बाद

फरवरी का महिना पपीते की खेती करने वाले किसनों के लिए बेहद जरूरी हो सकता है. जिस वजह से इस समय पपीते पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. अगर ध्यान नहीं दिया तो दूसरी खतरनाक बीमारियां फलों के लगने से पहले ही बर्बाद कर देंगी.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक पपीते कुछ खास विधि से करेंगे तो इससे अच्छी पैदावार मिल सकती है. जो किसान अक्टूबर में पपीते की खेती करते हैं, उनके पौधा का विकास सर्दियों की वजह से धीमा हो जाता है. जिस वजह से निराई और गुड़ाई की ज्यादा जरूरत होती है. जिसके बाद प्रति पौधे में लगभग 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्टेट, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल पौधे के तने से करीब एक से डेढ़ फीट की रूडी पर गोला बना क्र करना चाहिए. इसके बाद जरूरत के हिसाब से हल्की हल्की सिंचाई करते रहें.

पपीते के पौधे के पास बनाया गया पपीता रिंग में नीम का का तेल 2 फीसद करीब आधे लीटर स्टीकर में मिलाकर एक एक महीने के अंतराल में करीब 8 महीनों तक स्प्रे करते रहें.

ऐसे करें इलाज, नहीं होगा नुकसान

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि, हाई क्वालिटी के फल और पपीतों के पौधों में रोगों से लड़ने के गुण होने जरूरी हैं. इन गुणों को बढ़ाने के लिए दस ग्राम यूरिया के साथ पांच ग्राम जिंक सल्फेट और पांच ग्राम बोरान को प्रति लीटर पानी के हिसाब से अच्छे से घोलकर एक एक महीने के गैप में स्प्रे करें. ऐसा आपको अगले आठ महीने तक करना होगा. इस बात का ध्यान रखें कि, जिंक सल्फेट और बोरोन एक साथ ना घोलें. इन्हें अलग-अलग ही घोलें. क्योंकि ये जमने लगते हैं I

फरवरी का महीना सबसे जरूरी

जड़ गलन अब तक की पपीते में लगने वाली सबसे भयानक बीमारियों में से एक है. इससे निपटने के लिए जरूरी है कि, हेक्साकोनाजोल की लगभग दो मिली दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर एक एक महीने के गैप में मिट्टी में खूब अच्छी तरह से डालें. ताकि मिट्टी अच्छी तरह से भींग जाए. आपका ऐसा आठ महीनों तक करते रहना है. इसका मतलब इस घोल से मिट्टी को लगातार भिगोते रहना है. अगर आपके पपीते का पौधा बड़ा है तो उसके लिए लगभग पांच से छह लीटर दवा के घोल को डालने की जरूरत होती है.

पपीते लगाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अप्रैल तक का होता है. इसलिए फरवरी के महीने में पपीते की नर्सरी लगाने की सलाह दी जाती है.

अब आम खाने के लिए गर्मियों का इंतजार नहीं, पूरे साल मिलेगी जबरदस्त वैरायटी

आम का स्वाद और आम के लिए पूरे सीजन का इंतजार करना, सिर्फ एक आम प्रेमी ही समझ सकता है. वैसे आम की खेती से सिर्फ एक बार ही फल मिलता है. लेकिन उन आम प्रेमियों का क्या, जो पूरे साल आम की डिमांड करते रहते हैं. जिसे देखते हुए आम को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है. लेकिन यहां बात किसानों की करें तो उन्हें तो इसकी खेती से साल भर में सिर्फ एक बार ही कमाई होती है. लेकिन किसानों की इस समस्या का भी हल निकल चुका है. जहां देश में उपस्थित राजस्थान और कोटा के किसानों ने एक बड़ी उपलब्धी हासिल कर ली है I

जानकारी के मुताबिक कोटा और राजस्थान के किसानों ने आम की एक खास वैरायटी तैयार की है. जिसके चलते अब बिना सीजन के भी आम का बंपर उत्पादन किया जा सकेगा. इस आम की वैरायटी बारोमासी यानि की सदाबहार बताई जा रही है. आम की इस वैरायटी को साइंटिस्ट श्रीकृष्ण सुमन ने तैयार किया है. साइंटिस्ट की मानें तो इस वैरायटी के आम के पेड़ों से साल भर में कम से कम तीन बार उत्पादन हो सकेगा. इसका मतलब साफ है कि, अब आम की खेती से एक बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार मुनाफा कमाया जा सकेगा.

खास वैरायटी के आम की खास बातें

इस सदाबहार आम की प्रजाति एक तरह की बौनी प्रजातियों में से एक है. इसका मतलब इस तरह के पेड़ों की लंबाई ज्यादा ऊंची नहीं होती. इसे कीचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है. लंगड़े आम की तरह दिखने वाले सदाबहार आम का रंग भी नारंगी होता है. इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है. अगर कोई किसान अपनी एक हेक्टेयर की जमीन पर इस वैरायटी के आम के पेड़ों की खेती करता है तो इसे लगभग पांच से सात टन फलों की पैदावारी मिल सकती है I

हाल ही में कोटा में कृषि एंव किसान कल्याण विभाग ने दो दिवसीय कृषि महोत्सव प्रशिक्षण और प्रदर्शनी का आयोजन किया. इस दौरान साइंटिस श्रीकृष्ण सुमन ने भी सदाबहार आम के पेड़ को प्रदर्शनी में दर्शाया. उन्होंने बताया कि, यह पौधा अन्य आम के पौधों की किस्मों के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ता है और दो साल के अंदर ही फल देने लगता है. सदाबहार आम के लिए सिर्फ गोबर की खाद ही काफी है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, ऑफसीजन में इस किस्म के पेड़ में फल लदे होते हैं. जिसके चलते किसान साल में तीन बार मोटी कमाई कर सकते हैं I

लागत कम मुनाफा ज्यादा, ऐसे करें तरबूज की खेती

भारत में इस वक्त रबी की फसलों की कटाई का काम तेजी से चल रहा है. जिसका काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. जिसके बाद खेत खाली हो जाएंगे. ऐसे में किसान चाहें तो तरबूज की खेती करके कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. तरबूज की खेती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि, इसके लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है. वहीं भारत में गर्मियों के मौसम में ज्यादा डिमांड होने की वजह से इसके अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं.

अगर आप भी तरबूज की खेती करने का मन बना रहे हैं तो, रबी और खरीफ के सीजन के बीच के सीजन यानि कि जायद के सीजन में उगा सकते हैं. यह सीजन फरवरी से मार्च के बीच का होता है. तरबूज की खेती के लिए उसकी उन्नत किस्मों की बुवाई फायदेमंद होती है. इसके लिए खेती करने का सही तरीका भी आना चाहिए. तो चलिए फिर जानते हैं, तरबूज की खेती से जुड़ी अहम बातें.

इन राज्यों में होती है सबसे ज्यादा खेती

देश में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही, तरोताजा कर देने वाले तरबूज की डिमांड बढ़ जाती है. इसलिए इसकी खेती भी काफी ज्यादा बड़े पैमाने में की जाती है. इसकी खेती मुख्य रूप से यूपी, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान में की जाती है. अगर आप किसी अन्य फलों की खेती करते हैं तो उनके मुकाबले तरबूज की खेती करना आसान है. क्योंकि इसमें कम खाद, कम समय, और कम पानी की जरूरत पड़ती है. तरबूज की खेती के लिए गंगा, यमुना जैसी अन्य नदियों के किनारे खाली जगहों पर की जाती है.

तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी

ज्यादा तापमान वाली जलवायु तरबूज की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है. ज्यादा तापमान से फल जल्दी बढ़ते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक फलों के बीजों को अंकुरित होने के लिए कम से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान की जरूरत होती है. वहीं तरबूज की खेती के लिए रेतीली और दोमट जमीन अच्छी रहती है. इसके अलावा उसकी मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच होना चाहिए. अगर जमीन उपजाऊ नहीं है और बंजर है, तो भी इसकी खेती आराम से की जा सकती है.

तरबूज की उन्नत किस्मों के बारे में
तरबूज की वैसे तो कई तरह की उन्नत किस्में हैं, जो काफी समय और कम लागत में तैयार हो जाती हैं. इसके अलावा वो उत्पादन भी बढ़िया देती हैं. जिनके बारे में आपका भी जान लेना जरूरी है.

- **अर्का मानिक**

इस किस्म के तरबूज का विकास बैंगलौर में किया गया. यह किस्म जल्दी सड़ती नहीं है. तरबूज की यह किस्म प्रति हेक्टेयर 50 से 60 टन तक की उपज देती है.

- **अर्का ज्योति**

इस तरह के किस्म के तरबूज का भार 7 से 8 किलो तक होता है. साथ ही इसे काफी दिनों तक रखा भी जा सकता है. प्रति हेल्तेय्र 350 क्विंटल तक इसका उत्पादन किया जा सकता है.

- शुगर बेबी

शुगर बेबी किस्म के तरबूज के बीज काफी जल्दी तैयार हो जाते हैं. कम से कम सौ दिनों के बाद यह तोड़ने लायक हो जाते हैं. इसके फलों में बीज काफी कम होते हैं. 200 से 250 क्विंटल की उपज प्रति हेक्टेयर मिल सकती है.

- **डब्लू 19**

NRCH द्वारा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए यह किस्म सबसे अच्छी होती है. तरबूज की यह किस्म ज्यादा तापमान भी सहन कर सकती है. इसका फल काफी अच्छा और मीठा होता है. इसे दो से ढ़ाई महीने में तैयार किया जा सकता है. 40 से 50 टन की उपज प्रति हेक्टेयर में पाई जा सकती है.

- **आशायी यामातो**

जापान से लायी गयी इस किस्म के फलों का भार 6 से 9 किलो तक होता है. धारीदार और हल्के हरे रंग का छिलका इसकी पहचान है. 200 से 225 क्विंटल तक की उपज प्रति हेक्टर में मिल जाती है.

अगर चाहते हैं हाइब्रिड तरबूज की खेती

अगर आप हाइब्रिड तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो खेती से पहले खेत की जुताई करनी जरूरी है. इस तरह की खेती के लिए खेत को तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल का सहारा ले सकते हैं. आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि, कहत में पानी की मात्रा एकदम बराबर हो. यानि कि ना तो ज्यादा और ना ही कम. जिसके बाद आप नदियों की खाली जगह पर क्यारियां बना लें और जमीन में गोबर की खाद मिला दें. अगर रेत ज्यादा है तो ऊपर की स्थ को हटाकर मिट्टी में खाद मिला दें.

जानिए बुवाई का सही तरीका

तरबूज के बीजों की बुवाई अगर मैदानी क्षेत्रों में कर रहे हैं तो समतल भूमि का चयन करें, अगर बुवाई पर्वतीय क्षेत्रों में कर रहे हैं तो उपर की तरफ उठी हुई क्यारियों का चयन करें. इसके लिए दो से ढ़ाई मीटर चौड़ी क्यारी बनाई जाती है. जिसके किनारे डेढ़ सेंटीमीटर गहरे होते हैं. जिनमें बीजों को बोया जाता है. बुवाई की लाइन और आपसी दूरी कितनी हो यह तरबूज की किस्म पर निर्भर करता है.
सही खाद और उर्वरक का करें प्रयोग
तरबूज की खेती के लिए गोबर की खाद को रेतीली भूमि में मिलाया जाता है. यह काम आप जमीन तैयार करते वक्त भी कर सकते हैं. वहीं 70 से 80 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर के साथ फास्फेट और पोटाश की मात्रा 60-60 किलो प्रति हैक्टेयर होनी चाहिए. खाद उर्वरकों की मात्रा और उसकी शक्ति पर भी निर्भर करती है. उर्वरा शक्ति जमीन में ज्यादा हो तो उर्वरक और खाद की मात्रा को आप कम कर सकते हैं.

क्या हो सिंचाई के प्रबंध?

तरबूज की बुवाई के लगभग 15 से 20 दिनों के बाद सिचाई करना अच्छा होता है. नदियों के किनारे खेती करने की वजह से इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि वहां पर पहले से ही मिट्टी में नमी होती है.

कैसे करें तरबूज की तुड़ाई?

तरबूज की बुवाई के बाद करीब तीन से चार महीने के बाद इसे तोड़ने का काम शुरू हो जाता है. अगर फल कहीं दूर भेजे जाने हैं तो इन्हें पहले ही तोड़ लें. हालांकि फलों को दबाकर भी देख लें. इससे फल का कच्चा और पका होने का अंदाजा लगाया जा सकता है. इसके अलावा फलों को उनकी डंठल से अलग करने के लिए चाकू या फिर धारदार चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या होगा आय का लाभ?

तरबूज की पैदावार की अलग-अलग किस्में होती हैं. जो मार्केट में 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल बेचा जाता है. अगर आपने 35 से 40 क्विंटल भी तरबूज की उपज कर ली तो, इससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है.

तरबूज की उन्नत किस्मों के बारे में

तरबूज की वैसे तो कई तरह की उन्नत किस्में हैं, जो काफी समय और कम लागत में तैयार हो जाती हैं. इसके अलावा वो उत्पादन भी बढ़िया देती हैं. जिनके बारे में आपका भी जान लेना जरूरी है.

- अर्का मानिक

इस किस्म के तरबूज का विकास बैंगलौर में किया गया. यह किस्म जल्दी सड़ती तरबूज के पौधों में रोग भी लगते हैं. जिनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है. यह काम कैसे करना करना है, चलिए जान लेते हैं.

- तरबूज की खेती में कद्दू का लाल कीड़ा लग जाता है. जिससे बचाव के लिए कारब्रिल 50 डीएसटी का छिड़काव किया जा सकता है.
- तरबूज में अक्सर फल मक्खी नाम का रोग भी लग जाता है, जिस वजह से फल में छेद हो जाता है. इससे बचाव के लिए मेलाथियान 50 ईसी का छिड़काव किया जा सकता है.
- अगर तरबूज की पत्तियों में सफेत पाउडर जैसा नजर आए तो समझिये, इसमें बुकनी रोग लगा है. इसके निदान के लिए डायनोकेप 05% का छिड़काव किया जा सकता है.
- पोधे कि निचली सतह पर गुलाबी रंग के पाउडर की तरह दिकाई देने वाला डाउनी मिल्ड्यू नाम का रोग होता है. इससे बचने के लिए मैंकोजेब का छिड़काव हफ्ते में तीन से चार बार किया जा सकता है.
- फ्यूजेरियम विल्ट नाम के रोग से ग्रसित होकर पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है और गिर जाता है. अगर बीज लगाने से पहले खेतों में केप्टान का छिड़काव कर लें, तो इससे पौधे बच सकते हैं.

तरबूज की खेती से जुड़ी यह ऐसी जानकारी हैं, जो आपके बेहद काम आने वाली है. हमारे बताये हुए तरीकों से तरबूज की खेती करके आप इस सीजन खूब मालामाल हो सकते हैं.

है. तरबूज की यह किस्म प्रति हेक्टेयर 50 से 60 टन तक की उपज देती है.

- अर्का ज्योति

इस तरह के किस्म के तरबूज का भार 7 से 8 किलो तक होता है. साथ ही इसे काफी दिनों तक रखा भी जा सकता है. प्रति हेल्तेय्र 350 क्विंटल तक इसका उत्पादन किया जा सकता है.

- शुगर बेबी

शुगर बेबी किस्म के तरबूज के बीज काफी जल्दी तैयार हो जाते हैं. कम से कम सौ दिनों के बाद यह तोड़ने लायक हो जाते हैं. इसके फलों में बीज काफी कम होते हैं. 200 से 250 क्विंटल की उपज प्रति हेक्टेयर मिल सकती है.

- डब्लू 19

NRCH द्वारा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए यह किस्म सबसे अच्छी होती है. तरबूज की यह किस्म ज्यादा तापमान भी सहन कर सकती है. इसका फल काफी अच्छा और मीठा होता है. इसे दो से ढ़ाई महीने में तैयार किया जा सकता है. 40 से 50 टन की उपज प्रति हेक्टेयर में पाई जा सकती है.

- आशायी यामातो

जापान से लायी गयी इस किस्म के फलों का भार 6 से 9 किलो तक होता है. धारीदार और हल्के हरे रंग का छिलका इसकी पहचान है. 200 से 225 क्विंटल तक की उपज प्रति हेक्टर में मिल जाती है.

अगर चाहते हैं हाइब्रिड तरबूज की खेती

अगर आप हाइब्रिड तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो खेती से पहले खेत की जुताई करनी जरूरी है. इस तरह की खेती के लिए खेत को तैयार करना सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल का सहारा ले सकते हैं. आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि, कहत में पानी की मात्रा एकदम बराबर हो. यानि कि ना तो ज्यादा और ना ही कम. जिसके बाद आप नदियों की खाली जगह पर क्यारियां बना लें और जमीन में गोबर की खाद मिला दें. अगर रेत ज्यादा है तो ऊपर की स्थ को हटाकर मिट्टी में खाद मिला दें.

मशीनरी

किसानों को सस्ते में मिलेंगे कृषि यंत्र, सरकार दे रही 50% सब्सिडी

वेलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है. अब ऐसे में जहां एक तरफ युवाओं के सिर पर प्यार का खुमार चढ़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं और खूब सारा मुनाफा कमा रहे हैं.
आमतौर पर वेलेंटाइन वीक को गुलाबों का त्यौहार भी कह सकते हैं. जिस वजह से इसका बाज़ार भी तेजी पकड़े हुए है. हालांकि सर्दी और पाले की वजह से किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण आवक में कमी और कीमतों में बढ़ोतरी हो गयी है. देखा जाए तो इस वक्त बाजार में गुलाब अपनी कीमत से चार गुना ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है.
वेलेंटाइन में गुलाब किसानों की कमाई का एक बढ़िया जरिया बना हुआ है. मार्केट में एकदम से गुलाब की डिमांड बढ़ गयी है. जिसका सीधा फायदा फूलों की खेती करने वाले किसानों को हो रहा है. इतना ही नहीं देश की अलग-अलग मंडियों की बात करें तो गुलाब की कीमतें आसमान पर हैं. 10 से 15 रुपये में मिलने वाला गुलाब इस समय बाजार में कम से कम 100 से 150 रुपये में बिक रहा है. जिसकी वजह से किसानों की खूब बल्ले-बल्ले हो रही है.

गाजीपुर में आसमान छू रहे फूलों के दाम
वेलेंटाइन वीक के शुरू होते ही गाजीपुर में भी गुलाब के दामों ने आसमान छू लिया. इस वीक के पहले ही दिन से गुलाब की कीमत 50 रुपए तक हो गयी. ऐसे में किसान को भी इसका खूब फायदा हो रहा है. सिर्फ गुलाब ही नहीं बल्कि अन्य फूलों की कीमत भी लोगों से खूब वसूली जा रही है. किसानों की मानें तो जब आवक ज्यादा होता है और बिक्री कम होती है तो कीमतें भी कम हो जाती हैं. लेकिन कम आवक और ज्यादा डिमांड होने की वजह से कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी जाती है.

क्या है किसानों को अनुदान

वेलेंटाइन वीक गुलाब के अलावा जरबेरा के फूलों की भी जबरदस्त डिमांड होती है. जो प्रेमी जोड़ों की पहली पसंद भी है. इन दिनों किसान जरबेरा की ऊटी वैरायटी बाजार में बेच रहा है. एक एकड़ में जरबेरा की खेती लगभग 50 लाख की होती है. लेकिन बागवानी विभाग से इसे लेकर सब्सिडी भी जाती है. जिसके बाद इसकी लागत काफी कम हो जाती है. जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा जरबेरा की खेती की जाती है.
वेलेंटाइन वीक ना सिर्फ कपल्स के लिए बल्कि किसानों के लिए भी खूब मुनाफेदार साबित हो रहा है. इस सीजन में गुलाबों का यह व्यापार किसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो रहा है.

ड्रोन करेंगे खेती, इंसान करेंगे आराम, जानिए क्या है मास्टर प्लान

देशभर में ड्रोन के जरिये कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. इसी की तर्ज पर एक कम्पनी ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है. जिसमें खेती के लिए ड्रोन ही काफी होंगे. और इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी.

ताजा जानकारी के मुताबिक कृषि में इस्तेमाल किये जाने वाले ड्रोन को बनाने वाली आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने बड़ा समझौता किया है. यह समझौता कृषि सेक्टर में इंसानों के बजाय ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. महाराष्ट्र के वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ के साथ इस समझौते को किया गया है.

इस समझौते को लेकर कंपनी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि, इसका उद्देश्य ड्रोन को प्रद्योगिकी में आगे बढ़ाने के अलावा कृषि उत्पादन को बढ़ाने का है. साथ किसानों के बीच जागरूकता फैलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है.

पहले ही हुई थी साझेदारी की घोषणा

समझौते ज्ञापन की बात करें तो, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंद्र मणि और स्टार्ट-अप आईओटी का वर्ल्ड एविगेशन की तरफ से निदेश अनूप कुमार ने साइन किये. बता दें साल 2017 में इसी तरह की साझेदारी की घोषणा की गयी थी.

कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा

जानकारी के मुताबिक समझौता करने वाले दोनों पक्ष कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल करने को बढ़ावा देंगे. इसके अलावा कृषि प्रशिक्षण केंद्र और आरपीटीओ को बनाने के लिए मिलाकर काम किया जाएगा. आयोतेक वर्ल्ड के सह संस्थापक दीपक भारद्वाज के मुताबिक युनिवर्सिटी के साथ समझौते से कंपनी को ड्रोन टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा खोज करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा कृषि ड्रोन के लिए रिमोट पायलट आईओटी का वर्ल्ड वीएनएमकेवी के साथ मिलकर इसकी स्थापना में भागीदार होगा. आपको बता दें इससे देश में ड्रोन पायलट की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप का अपना अलग रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन है. इस ऑर्गनाइजेशन में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग के साथ ड्रोन पायलेट को लाइसेंस भी दिया जाता है.

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

बंजर और शुष्क भूमि में खेती को मिलेगा बढ़ावा, टीएनएयू ने तैयार किये लाल चंदन

तमिलनाडु में खास कृषि बजट में बंजर और शुष्क भूमि में खेती को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाया है. दरअसल तमिलनाडु कृषि विश्विद्यालय यानि की टीएनएयू ने फारेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च में सबसे ज्यादा फायदे देने वाले लाल चंदन के पौधे तैयार किये हैं.

टीएनएयू (TNAU) के कुलपति के मुताबिक तमिलनाडु ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. जोकि 17 फीसद से बढ़ाकर करीब 30 फीसद तक किया जाएगा. जिसमें लाल चंदन को उगाया जाएगा. बता दें लाल चंदन उगाने से किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. क्योंकि बाजार में लाल चंदन की लकड़ी की बिक्री पर काफी अच्छा रिटर्न मिलता है. वहीं सरकार की तरफ से प्राइवेट जमीनों पर लाल चंदन के पेड़ उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है

किसानों को मिलेगा अच्छा मुनाफा

जानकारी के मुताबिक एक बड़े लाल चंदन के पेड़ की लकड़ी की कटाई करने के लिए 18 साल का इंतजार करना होता है. लेकिन इंतजार के बाद हर पेड़ से 1 क्विंटल तक की लकड़ी मिलती है. जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है. एक एकड़ की जमीन में आप करीब तीन-तीन मीटर की दूरी पर करीब एक साथ 450 पेड़ उगा सकते हैं.

आपको बता दें कि, लाल चंदन के पौधे में तने से लेकर जड़ों तक में एक खास तरह की इंजीनियरिंग प्रणाली शामिल की गयी है. इसकी मदद से ज्यादा उपज मिल सकेगी. इस लाल चंदन की खास किस्म को तेजी से बढ़ने वाले पौधों की प्रजातियों के लिए विकसित किया गया है.

लाला चंदन के इस पौधे को विकसित करने के पीछे कृषि भूमि से बेहद दुर्लभ, और संकट से घिरी पेड़ों की प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देना है. साइंटिस्ट बताते है कि, अच्छे तरीके से किये गये पौधों का रोपण, ड्रिप से सिंचाई और अच्छे जड़ प्रबंधन के तरीकों से लाल चंदन के विकास को बढ़ावा मिल सकता है.

फसलों पर गर्मी नहीं बरपा पाएगी सितम, गेहूं की नई किस्मों से निकाला हल

फरवरी के महीने में ही बढ़ते तापमान ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है. अब ऐसे में फसलों के बर्बाद होने के अनुमान के बीच एक राहत भरी खबर किसानों के माथे से चिंता की लकीर हटा देगी.

बदलते मौसम और बढ़ते तापमान से ना सिर्फ किसान बल्कि सरकार की भी चिंता का ग्राफ ऊपर है. इस साल की भयानक गर्मी की वजह से कहीं पिछले साल की तरह भी गेंहूं की फसल खराब ना हो जाए, इस बात का डर किसानों बुरी तरह से सता रहा है. ऐसे में सरकार को भी यही लग रहा है कि, अगर तापमान की वजह से गेहूं की क्वालिटी में फर्क पड़ा, तो इससे उत्पादन भी प्रभावित हो जाएगा. जिस वजह से आटे की कीमत जहां कम हो वाली थी, उसकी जगह और भी बढ़ जाएगी. जिससे महंगाई का बेलगाम होना भी लाजमी है. आपको बता दें कि, लगातार बढ़ते तापमान पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था.

इन सब के बीच अब सरकार के साथ साथ किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वो कर दिखाया है, जो किसी ने भी सोचा भी नहीं था. दरअसल आईसीएआर ने गेहूं की तीन ऐसी किस्म को बनाया है, जो गर्मियों का सीजन आने से पहले ही पककर तैयार हो जाएंगी. यानि के सर्दी का सीजन खत्म होने तक फसल तैयार हो जाएगी. जिसे होली आने से पहले ही काट लिया जाएगा. इतना ही नहीं आईसीएआर के साइंटिस्टो का कहना है कि, गेहूं की ये सभी किस्में विकसित करने का मुख्य कारण बीट-द हीट समाधान के तहत आगे बढ़ाना है.

पांच से छह महीनों में तैयार होती है फसलें

देखा जाए तो आमतौर पर फसलों के तैयार होने में करीब पांच से छह महीने यानि की 140 से 150 दिनों के बीच का समय लगता है. नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा गेहूं की बुवाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, इसके अलावा नवंबर के महीने के बीच में धान, कपास और सोयाबीन की कटाई मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, एमपी और राजस्थान में होती है. इन फसलों की कटाई के बाद किसान गेहूं की बुवाई करते हैं. ठीक इसी तरह युपू में दूसरी छमाही और बिहार में धान और गन्ना की फसल की कटाई के बाद ही गेहूं की बुवाई शुरू की जाती है.

महीने के आखिर तक हो सकती है कटाई

साइंटिस्टो के मुताबिक गेहूं की नई तीन किस्मों की बुवाई अगर किसानों ने 20 अक्टूबर से शुरू की तो, गर्मी आने से पहले ही गेहूं की फसल पककर काटने लायक तैयार हो जाएगी. इसका मतलब अगर नई किस्में फसलों को झुलसा देने वाली गर्मी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगी, जानकारी के मुताबिक मार्च महीने के आखिरी हफ्ते तक इन किस्मों में गेहूं में दाने भरने का काम पूरा कर लिया जाता है. इनकी कटाई की बात करें तो महीने के अंत तक इनकी कटाई आसानी से की जा सकेगी.

जानिए कितनी मिलती है पैदावार

आईएआरआई के साइंटिस्ट ने ये ख़ास गेहूं की तीन किस्में विकसित की हैं. इन किस्मों में ऐसे सभी जीन शामिल हैं, जो फसल को समय से पहले फूल आने और जल्दी बढ़ने में मदद करेंगे. इसकी पहली किस्म का नाम एचडीसीएसडब्लू-18 रखा गया है. इस किस्म को सबसे पहले साल 2016 में ऑफिशियली तौर पर अधिसूचित किया गया था. एचडी-2967 और एचडी-3086 की किस्म के मुकाबले यह ज्यादा उपज देने में सक्षम है. एचडीसीएसडब्लू-18 की मदद से किसान प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सात टन से ज्यादा गेहूं की उपज पा सकते हैं. वहीं पहले से मौजूद एचडी-2967 और एचडी-3086 किस्म से प्रति हेक्टेयर 6 से 6.5 टन तक पैदावार मिलती है.

नई किस्मों को मिला लाइसेंस

सामान्य तौर पर अच्छी उपज वाले गेंहू की किस्मों की ऊंचाई लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर होती है. इस वजह से लंबी होने के कारण उनकी बालियों में अच्छे से अनाज भर जाता है. जिस करण उनके झुकने का खतरा बना रहता है. वहीं एचडी-3410 जिसे साल 2022 में जारी किया गया था, उसकी ऊंचाई करीब 100 से 105 सेंटीमीटर होती है. इस किस्म से प्रति हेल्तेय्र के हिसाब से 7.5 टन की उपज मिलती है. लेकिन बात तीसरी किस्म यानि कि एचडी-3385 की हो तो, इस किस्म से काफी ज्यादा उपज मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं एआरआई ने एचडी-3385 जो किसानों और पौधों की किस्मों के पीपीवीएफआरए के संरक्षण के साथ रजिस्ट्रेशन किया है. साथ ही इसने डीसी एम श्रीरा का किस्म का लाइसेंस भी जारी किया है.

कम किये जा सकते हैं आटे के रेट

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर किसानों ने गेहूं की इन नई किस्मों का इस्तेमाल खेती करने में किया तो, गर्मी और लू लगने का डर इन फसलों को नहीं होगा. साथी ही ना तो इसकी गुणवत्ता बिगड़ेगी और ना ही उपज खराब होगी. जिस वजह से गेहूं और आटे दोनों के बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल किया जा सकता है.

सोने चांदी से कम नहीं यह सब्जी, जानिये क्यों है अमीरों की पहली पसंद

आजकल बाजार में तरह तरह की सब्जियां देखने को मिल रही हैं. जिनका ना सिर्फ रंग रूप बाकियों से अलग होता है बल्कि महंगी भी होती हैं. हालांकि खाने की चीज कोई भी हो, ज्यादातर महंगी ही होती है. लेकिन एक सब्जी ऐसी भी है, जो इतनी महंगी है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है.

हम बात कर रहे हैं हॉप शूट नाम की सब्जी की. विटामिन् ई, बी, सी और खनिज तत्वों से भरपूर इस सब्जी को अमीरों की सब्जी क्यों कहते हैं, आप इस बारे में तो जरुर सोच रहे होंगे. तो आपको बता दें कि, हॉप शूट की सोने चांदी से कम नहीं है. इस सब्जी की कीमत इतनी ज्यादा है कि, इसे सिर्फ आमिर लोग ही अपनी प्लेट में सजाना पसंद करते हैं. बात इसकी कीमत की करें तो ये लाख रुपये के करीब है. महानगरों में मिलने वाली इस सब्जी को खाना है तो इससे पहले इसे ऑर्डर करना पड़ता है.

हॉप शूट के बारे में

हॉप शूट के बारे में बताएं तो यह दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में शुमार है. बाजार में इसकी कीमत हमेशा 80 हजार से करीब एक लाख रुपये प्रति किलो तक रहती है. जिस वजह से सिर्फ बड़े और खानदानी लोग ही इसे खरीदने की हिम्मत दिखा पाते हैं. इसकी कीमत जितनी ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा इसकी खेती करने में मेहनत लगती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक एल्कोहल को बनाने में इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने में ही हॉप शूट का इस्तेमाल किया जाता है.

कैंसर से लड़ने में करे मदद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉप शूट में ज्यादा मात्रा में विटामिन ई, बी, ससी समेत कई तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट के भी गुण होते हैं. इसके अलावा इसमें कई तरह की बिमारियों से लड़ने की भी ताकत होती है, जिससे शरीर मजबूत बनता है. अगर आपको चिंता, तनाव, टेंशन, बेचैनी, चिडचिडापन या फिर घबराहट की समस्या है तो, हॉप शूट के सेवन से इससे छुटकारा पाया जा सकता है. इसकी अनगिनत खूबियों की वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो हॉप शूट खाने से शरीर को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है.

इन देशों में हॉप शूट को समझा जाता है कचरा

शोध के मुताबिक हॉप शूट को खाने से मसल्स में दर्द और बदन में दर्द की शिकायत से आराम मिलता है. इसके अलावा डायजेशन की समस्या से निपटने में भी हॉप शूट काफी मददगार है. नींद से जुड़ी समस्या का समाधान भी इस सब्जी के पास है. हॉप शूट को कच्चा भी खाया जाता है. खाने में कड़वा टेस्ट होने की वजह से इसका आचार भी बनाकर खाया जा सकता गौ. इस सब्जी की कीमत काफी ज्यादा है, जिसके बाद भी ब्रिटेन समेत कई देशों में इसे कचरा समझा जाता है.

हॉप शूट सब्जी के बारे में ये कुछ ऐसी खास बाते हैं, जिनको जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है.

सरकारी नीतियां

हरियाणा कृषि बजट की अहम घोषणाएं, किसानों की होगी अच्छी आय

केंद्र सरकार ने अपने वित्त वर्ष साल 2023 से 2024 के लिए 1 फरवरी को नया बजट पेश किया था. जिसके बाद देश के अन्य राज्यों की सरकारें भी नये साल के बजट के साथ अपने मास्टर प्लान बताने लगी है. जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और हरियाणा का बजट भी शामिल है.

जहां हरियाणा की बात की जाए, तो राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हरियाणा का नया बजट गुरुवार को पेश कर चुके हैं. वित्त वर्ष साल 2023 से 2024 के लिए पशुपालन के साथ कृषि, बागवानी, सहकारिता और बागवानी मुख्य बिंदु रहे. इन सभी क्षेत्रों के लिए सरकार की तरफ से 8 हजार 316 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्ताव रखा गया. हालांकि यह प्रस्ताव पीछले साल के बजट से लगभग 19 फीसद ज्यादा है. ऐसे में वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह की कोई भी नई योजना का ऐलान नहीं किया है.

इन सबके बीच किसानों के हित के बारे में सोचते हुए सरकार ने पहले से चली आ रही योजनाओं में कुछ खास बदलाव करते हुए राहत अनुदान पैकेज में बढ़ोतरी कर दी गयी है.

जानिए क्या हैं कृषि बजट की महत्वपूर्ण योजनाएं

- हरियाण में भूजल संकट गहराता जा रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन में धान की सीधी बिजाई का प्रस्ताव सामने रखा है.
- इस साल राज्य में लगभग दो लाख हेक्टेयर के हिसाब से रकबा धान की सीधी बिजाई का मास्टर प्लान है.
- ढेंचा खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा.
- ढेंचा खेती के लिए लगने वाली लागत सरकार ने प्रति एकड़ के हिसाब से 720 रुपये रखी है. जिसके तहत किसानों को लगभग 80 फीसद का अनुदान दिया जाएगा.
- हरियाणा में गर्मीं के सीजन में मूंग का उत्पादन बढ़ाने का भी प्लान है.
- मूंग के अच्छे उत्पादन के लिए करीब एक लाख एकड़ से ज्यादा जगह को कवरेज किया जाएगा.
- ड्रोन तकनीक के जरिये खेती किसानी से जुड़े काम को आसान बनाने में मदद दिलाई जाएगी.
- 500 युवा किसानों को ड्रोन चालने की ट्रेनिंग का भी प्रस्ताव रखा गया है.
- लगभग 50 हजार एकड़ जमीन को कृषि योग्य बनाया जाएगा.
- अच्छी गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए हनी क्वालिटी लैब की स्थापना की जाएगी.
- शहद व्यापार में नीति भी लागू की जाएगी.
- पंचकूला, पिनगवां, नूह, झज्जर और मणिपुर में बागवानी फसलों के लिए तीन सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- पराली खरीद के लिए 1 हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया गया है.
- पराली जलाने से जुड़ी समस्या को निपटाने के लिए चयनित एजेंसियों को खर्चों के लिए 15 सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से दिया जाएगा.

नेचुरल फार्मिंग की ओर ज्यादा ध्यान

कृषि में लगने वाली लागत को कम करने के लिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, गाय पालन से लेकर कम बजट में अच्छी फसलों का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसी तरफ पर हरियाणा की सर्कन ने भी अपने इस नये बजट में 20 हजार एकड़ रकबे को नेचुरल फार्मिंग के लिए निर्धारित किया है.

बता दें सरकार के इस कदम से कृषि विशेषज्ञों को मदद मिलेगी. इसके अलावा जींद और सिरसा जिले में कुल तीन नेचुरल फार्मिंग से जुड़े ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे.

पशु पालन के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं

हरियाणा को दूध के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. किसान अपनी किसानी के साथ पशु पालन का भी काम करते हैं. हालांकि पशु पालन के विकास को लेकर सरकार पहले से ही कई तरह की योजनाएं चला रही है. लेकिन वित्त वर्ष 2023 से 2024 में इस सेक्टर में विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान की भी शुरुआत करने का प्लान है.

- पशुधन की स्वास्थ्य से जुड़ी सुरक्षा के लिए 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा युनिट की शुरुआत की जाएगी.
- राज्य के कई हिस्सों में पशु चिकित्सा पालीटेक्निक की भी स्थापना की जाएगी.
- दो हाईटेक वेटनरी पेट क्लिनिक फरीदाबाद और गुरुग्राम में शुरू किया जाएगा.
- हरियाणा गौ सेवा आयोग ने 4 सौ करोड़ का बजट आवारा पशुओँ की सुरक्षा के लिए देने का ऐलान किया है. यह बजट पहले सिर 40 करोड़ रुपये ही था.
- ग्राम पंचायतों की सहमती के बाद नई गौशालाओं की स्थापना की जाएगी.

नहीं झेलनी पड़ेगी पानी की किल्लत

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि, सरकार ने पिछले कुछ सालों में सूक्ष्म सिंचाई की तरफ खास ध्यान दिया है. जिससे भूजल को संरक्षित करने में काफी मदद मिली है. जिसके बाद इसी कड़ी में बजट 2023 से 2024 के लिए सरकार उन गांवों में एक हजार पोजोमीटर की स्थापना करवाएगी जहां पानी की किल्लत है. इस योजना को नाम अटल भूजन योजना रखा गया है.

हरियाणा सरकार का इस साल करीब ढ़ाई लाख एकड़ कृषि क्षेत्रफल को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ेगी. जिसके लिए 4 हजार ऑन फार्म वाटर टैंक का निर्माण किया जाएगा. बात गन्ने के उत्पान को बढ़ाने की करें तो उसके लिए भी सरकार के पिटारे से काफी कुछ निकला है. जहां राज्य में 2 लाख एकड़ पर जल संचय के लिए कई तरह के ढांचों की स्थापना करवाई जाएगी.

यूपी के बजट में किसानों पर दिया गया है ख़ास ध्यान; जानें क्या है नई घोषणाएं

यूपी सरकार द्वारा साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया जा चुका है. आंकड़ों से पता चला है कि इस बार सरकार ने बजट में 7 लाख करोड़ रुपए का बताया है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है.यह बजट सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया जिन्होंने सातवीं बार लगातार यह बजट पेश किया है. यूपी सरकार द्वारा लाए गए इस बजट में सबसे पहले और कई महत्वपूर्ण बातें किसानों पर की गई हैं.

बजट पेश करते समय सुरेश खन्ना ने कुछ आंकड़े सामने रखे जिनके अनुसार कहा गया है कि यूपी में लगभग 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इसी के चलते प्रदेश दूध, गन्ना, चीनी प्रोडक्शन और इथेनॉल की आपूर्ति में देश में पहले नंबर पर है.साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डीवीडी के जरिए किसानों को डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने वाला उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसमें किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे जमा किए हैं.

इस बजट में किसानों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई साथ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई जो इस प्रकार से हैं;

1. सरकार द्वारा 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल'' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसके तहत किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा.साल 2023-24 में यूपी सरकार ऐसी 170000 किसान पाठशाला में आयोजित करेंगी जिनमें उन्हें यह जानकारी दी जाएगी.
1. यूपी सरकार ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631 करोड़ 93 लाख रूपए देने की बात कही है.
2. यूपी सरकार नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग योजना को काफी महत्व दे रही है और इसके तहत राज्य में 49 जिलों में प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जो गौ आधारित है. इस बजट में सरकार ने इस योजना को 113 करोड़ 52 लाख रूपए प्रस्तावित किए हैं.
3. सरकार ने इस बजट में निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली आपूर्ति करवाने की बात भी कही है और इस योजना को पूरा करने के लिए 1950 करोड रुपए बजट में रखे गए हैं.
4. यूपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख रूपए का बजट रखा गया है.
5. आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए भी सरकार ने अच्छा खासा बजट इस बार निकाला है जो 100 करोड रुपए है.
6. सरकारों को उनकी फ्रॉक का इंश्योरेंस देना भी योगी सरकार का हमेशा से महत्व रहा है और इसीलिए इस बजट में नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है.
7. इन सबके अलावा सिंचाई और कृषि शिक्षा के लिए भी सरकार ने अलग से कई तरह की योजनाएं बनाने का फैसला किया है जिनके तहत बजट का आवंटन किया जाएगा.

जैसा कि बताया गया है कि यूपी एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने DBT के जरिए किसानों के खाते में सबसे ज्यादा पैसे डाले हैं.
आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2022- 23 में पीएम सम्मान निधि से 51 हजार 639.68 करोड़ से ज्यादा अमाउंट DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई. अभी के बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 7 हजार 248 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित है.
अर्थशास्त्र एक्सपर्ट डॉक्टर मुलायम सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि दूध, गन्ना और चीनी के उत्पादन में यूपी हमेशा से ही नंबर वन रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाए जाने वाली राशि को बहुत ही सराहनीय कदम बताया है. इसके अलावा उन्होंने इस बजट पर एक और टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नई घोषणाएं करने की बजाय अपनी पिछली उपलब्धियों को ज्यादा बनवाया है.
इसके अलावा उन्होंने छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए की बजट घोषणा करने को भी किसानों के लिए एक अच्छा कदम बताया है.

512 किलो प्याज बेचकर किसान को मिला केवल 2 रुपए का चेक

हाल ही में महाराष्ट्र के नासिक से एक बहुत ही ज्यादा चौका देने वाली खबर सामने आई है. सोलापुर जिले के 58 वर्षीय किसान राजेंद्र तुकाराम प्याज की खेती करने वाले एक साधारण से किसान हैं. हाल ही में वह सोलापुर APMC में अपने 512 किलो प्याज बेचने के लिए अपने गांव से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंचे और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि उन्हें 1 किलो प्याज के लिए सिर्फ ₹2 कीमत मिली.

512 किलो प्याज से हुआ केवल ₹2 मुनाफा

सभी तरह के खर्चे निकालने के बाद जब राजेंद्र तुकाराम ने अपना मुनाफा जोड़ा तो वह मात्र 2.49 रुपए था और इसके लिए भी उन्हें 15 दिन बाद का एक पोस्ट डेटेड चेक थमा दिया गया जिस पर कीमत ₹2 लिखी गई थी क्योंकि बैंक राउंड फिगर में ही पैसा अदा करता है और वह 49 पैसे किसान को नहीं दे सकते हैं.

राजेंद्र तुकाराम को यह पैसा सीधा ट्रेडर की तरफ से दिया जाएगा और उन्हें यह पैसा लेने में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अपने पूरे प्याज की फसल का दाम ₹512 दिया गया था जिसमें से लगभग ₹509 ट्रेडर ने ट्रांसपोर्ट, लोडिंग और वजन आदि करने के लिए काट लिया.

तुकाराम ने इस फसल पर खर्च किए थे ₹40000
आगे बातचीत करते हुए राजेंद्र ने बताया कि उन्हें 512 किलो प्याज उगाने के लिए लगभग ₹40000 खर्च करने पड़े थे क्योंकि आजकल और उर्वरक और बीज आदि सभी चीजों का मूल्य बढ़ चुका है.
APMC ने बताया कारण
तुकाराम को एक पोस्ट डेटेड चेक देने का कारण बताते हुए APMC ने कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी तरफ से सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड किया जा चुका है जिसके तहत इसी तरह से चेक दिए जाते हैं.उन्होंने बताया कि मूल्य कितना ही हो वह चेक से ही चुकाया जाता है और वह पहले भी इतने छोटे अमाउंट का चेक किसानों को दे चुके हैं.
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि तुकाराम जो प्याज लेकर आए थे वह अच्छी क्वालिटी के नहीं थे इसीलिए उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल पाया. अच्छी क्वालिटी के प्याज लगभग ₹18 प्रति किलोग्राम के हिसाब से APMC खरीद लेता है.

क्या है एक्सपर्ट की राय?

एक्सपर्ट की मानें तो उनका कहना है कि भारत में आज भी केवल पूरी फसल में से लगभग 25% ही उत्तम क्वालिटी की होती है और लगभग 30% फसल केवल मीडियम क्वालिटी की होती है और बाकी सारी फसल बहुत ही निम्न स्तर की उगती है. आंकड़ों की मानें तो प्याज की फसल में प्याज के क्विंटल तो बढ़ गई हैं लेकिन क्वालिटी आधी हो गई है. साल 2022 में 15000 क्विंटल प्याज़ की फसल हुई तो वहीं 2023 में यह बढ़कर 30000 क्विंटल हो गई है.लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी गिर गई है कि एक ही साल में मूल्य 1850 प्रति क्विंटल से गिर कर 550 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है.

कुछ समय पहले ग्राम पंचायत ने चिट्टी लिख सरकार से इस पर संज्ञान लेने की बात कही है.इस चिट्टी में किसानों को प्याज़ की फसल के लिए मुआवजा देने की बात भी कही गई है.किसानों ने पंचायत को यह शर्त ना पूरी होने पर आत्महत्या तक करने की धमकी दे दी है.
पंचायत ने बताया है कि पिछले 2 हफ्ते से इस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया गया है. राज्य के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल को भी इस मामले पर नज़र डालते हुए सरकार द्वारा फसल खरीदने की मांग भी रखी है.

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग, 20 मार्च को होगा हल्लाबोल

जल्द से जल्द स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने हुंकार भर दी है. जिसे लेकर वो ससंद में 20 मार्च को घेराव करते हुए हल्ला बोलेगी.

कई मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने 20 मार्च को संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है. अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि, देश में कसानों की ऋण से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि ऋणराहत आयोग का गठन किया जाए. आपको बता दें कि, एआईकेएस के राज्य अध्यक्ष ने जूलूस का नेतृत्व किया. यह जुलूस कासरगोड से लेकर त्रिशूर तक निकाला गया. इस दौरान ध्यक्ष जे. वेणुगोपालन नायर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, अच्छे दिन लाने के लिए कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाये जा रहे. देश के पीएम ने अपने एक साल पुराने वादों को अब तक पूरा नहीं किया. जो किसानों को धोखा देने के बराबर है.

उन्होंने कहा कि, किसानों की मांग कृषि उपज के लिए एमएसपी की क़ानूनी गारंटी है. ज्यादातर किसान अपनी उपज को उत्पादन में लगाई हुई लागत से कम में बेचने को मजबूर हैं. जिस वजह से वो कर्ज के मकड़जाल में फंसते चले जा रहे हैं. इससे बचने और कर्ज से निपटने के लिए केंद्र सरकार से अखिल भारतीय किसान सभा ने ऋण राहत आयोग के गठन की मांग उठायी है.

इसके अलावा उनका कहना है कि, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू करना चाहिए. क्योंकि यह भी एक बेहद जरूरी मांग है. केंद्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए अन्य किसानों से भी इस विरोध में शामिल होने की बात कही.

किसानों को लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार के इस फैसले से मिलेगा डबल फायदा

केंद्र सरकार की ओर से उन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो जूट की खेती करते हैं. दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि सरकार का ये फैसला बेहद अहम है, जो लगभग 40 लाख जूट के किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है.

केंद्र सकरार ने पैकेजिंग में जूट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करने के नियमों को आगे बढ़ाने पर मुहर लगा दी है. इन नियमों के अनुसार खाने पीनें की 100 फीसद चीजों और चीनी की 20 फीसद पैकिंग जूट के बैग में करनी जरूरी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुई.

ये भी देखें: बागवानी के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हर किसान कर सकता है अपनी कमाई दोगुनी

कैबिनेट ने जूट को साल 2022 से 2023 के लिए पैकेजिंग में जूट का जरूरी रूप से इस्तेमाल करने और इसके आरक्षण से जुड़े नियमों को मंजूरी दी है. इस फैसले से सबसे ज्यादा राहत जूट मिलों और अन्य इकाइयों में काम करने वाले करीब तीन से चार लाख श्रमिकों को मिलने वाली है. इसके अलावा लाखों किसानों के परिवारों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा जूट के अनिवार्य इस्तेमाल से पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि जूट एक ऐसा फाइबर है, जो पूरी तरह से नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है.

अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है जूट

पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, असम और मेघालय के लिए जूट बेहद जरूरी है. क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था जूट पर ही टिकी हुई है. वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी जूट बेहद महत्वपूर्ण है. जूट पैकेजिंग यानी की जेपीएम अधिनियम के तहत आरक्षण नियम जूट क्षेत्र में करीब 3.7 लाख श्रमिकों के अलावा लाखों जूट किसानों के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध करवाता है.

9 हजार करोड़ रुपये की है खरीद

बात जेपीएम अधिनियम की करें तो 1987 जूट किसानों, जूट से बने सामान और कामगरों में लगे श्रीमोकों के हित में है. जूट के उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 75 फीसद जूट से बने बोर हैं. जिनमें से करीब 85 फीसद की आपूर्ति भारतीय खाध्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों के द्वारा की जाती है. बता दें कि सरकार खाने की चीजों की पैकेजिंग के लिए हर साल लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के जूट के बोरे खरीदती है. इतना ही नहीं इससे जूट कामगारों और जूट किसानों को उनकी उमज के लिए बाजार को सुनिश्चित किया जाता है.

दिया जाता है लीगल फ्रेमवर्क

भारत और गुयान के बीच केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हवाई सर्विस एग्रीमेंट पर भी साइन करके अपनी सहमती जता दी है. जानकारी के लिए बता दें कि, गुयाना के साथ हुए हवाई समझौते पर साइन करने से दोनों देशों के बीच होने वाली हवाई सेवाओं के लिए एक रूपरेखा तय भी की जाएगी. हवाई सर्विस समझौते की बात करें तोम यह एक ऐसा एग्रीमेंट है, जहां दोनों देशों के बीच में एयर ऑपरेशंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क दिया जाता है.

भारत सरकार करती है इसका गठन

अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन साल 1944 पर सम्मेल में हुए बदलाव से जुड़े अनुच्छेद 3 बीआईएस और अनुछेदन 50 ए के अलावा अनुच्छेदन 56 पर तीन तरह के प्रोटोकॉल के रॉटिफिकेशन को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दी है. इसके अलावा देश के 22वें लॉ आयोग के कायलिय को भी 31 अगस्त साल 2014 तक बढ़ाने की मंजूरी मंत्रीमंडल ने दे दी है. आपको बता दें कि, देश का लॉ आयोग एक तरह का नॉन सांविधिक निकाय है. भारत सरकार की तरफ से इसका गठन किया जाता है.

गोबर उत्पादकों की होगी हाई लेवल पर बिक्री, यहां खुला देश का पहला शोरूम

गोबर उत्पादकों की होगी हाई लेवल पर बिक्री, यहां खुला देश का पहला शोरूम

गोबर से बने उत्पादकों की अच्छी बिक्री के लिए अब देश में पहला शोरूम खुल चुका है. छोटे मॉल जैसा दिखने वाले इस अनोखे शोरूम में पूजा पाठ से लेकर हवन सामग्री और गौ काष्ठ, अगरबत्ती तक की चीजें आसानी से मिल जाती हैं.

छत्तीसगढ़ के इस शोरूम की शुरुआत होते ही कई महिलाएं इस बिजनेस से जुड़ चुकी हैं. जिनक कहना है कि, वो जो भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन्हें अब एक ब्रांड के तौर पर देखा जाएगा. जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इस बिजनेस को बढ़ाने में राज्य सरकार महिलाओं की बढ़ चढ़कर मदद कर रही है.

महिलाओं ने अपनाया नया बिजनेस आइडिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की महिलाओं ने इस नये बिजनेस आइडिया को अपनाया भी और धरातल पर उतारा भी. जहां गोबर से बने उत्पादों को बेचने के लिए इस एक्सक्लूसिव शोरूम को खोला गया है. इस शोरूम का नाम गोधन एम्पोरियम रखा गया है. जहां वर्मी कम्पोस्ट तो बेचा ही जा रहा है, इसके अलावा गौ काष्ठ, कंडे, अगरबत्ती और गोबर से बने पेंट भी बेचा जा रहा है. जहां शहर के में चौराहे पर गोधन एम्पोरियम पिछले तीन साल से चल रहा है. इस शोरूम को चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में ही दी गयी है. यहां पर काम करने वाली महिलाओं की आमदानी की बात करें तो, वो अब तक करीब 12 लाख रुपये तक कमा चुकी हैं.

रोज आते है कई ग्राहक

गोधन एम्पोरियम में लोग पूजा पाठ और हवन का समान खरीदने आते हैं. वहीं राज्य के जिन लोगों को लिट्टी चोखा पसंद होता है, वो यहां से गोबर के कंडे खरीदने आते हैं. बात वर्मी कम्पोस्ट की तो उसका इस्तेमाल भी शहरी क्षेत्र में लोग घरों की क्यारियों, गमलों और बागवानी के लिए कर रहे हैं. इस शोरूम में मिलने वाला पेंट काफी अलग है. इसमें तापमान को रोकने की क्षमता है, जिस वजह से इसकी डिमांड भी काफी रहती है. इन्हीं खूबियों की वजह से इस शोरूम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. आज इस शोरूम में हर रोज लगभग 50 से 60 ग्राहक आते हैं. हालांकि लगातार गोबर से बनी चीजों की बढ़ती लोकप्रयिता को देखते हुए यहां की चीजों की बिक्री और भी बढ़ सकती है.

अब तक हो चुकी है लाखों की आमदनी

गोधन एम्पोरियम लगातार तीन सालों से चल रहा है. इन तीन सालों में अब तक की हुई आमदनी की बात करें, तो करीब 12 लाख 49 हजार रूपये यहां की महिलाएं कमा चुकी हैं.

- साल 2020 से 2021 में 4 लाख 50 हजार की आमदनी हुई.
- साल 2021 से 2022 में 4 लाख 87 हजार की आमदनी हुई.
- साल 2022 से 2023 में अब तक 3 लाख 12 हजार रुपयों की आमदनी हो चुकी है.

इस शोरूम से हर समूह की महिलाएं लगभग 40 हजार रुपये तक की कमाई कर रही हैं. या शोरूम हफ्ते में एक दिन यानि की मंगलवार के दिन बंद रहता है.

गोधन एम्पोरियम में एक छत के नीचे गोबर से बनी चीजों का फायदा लोगों को मिल रहा है. साथ ही महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है. शोरूम में गोबर से बने उत्पादों में बढ़ोतरी हो रही है. गोधन एम्पोरियम अंबिकापुर शहरी गोठान का हिस्सा है, जिसे गौठान से ही जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है. समूह की ये महिलाएं अंबिकापुर सिटी लेवल फेडरेशन की मेम्बर भी हैं. बता दें यह फेडरेशन सफाई के लिए काम करता है. जहां गोबर का पेंट और दोना पत्तल बनाने की यूनिट भी शुरू हो चुकी है. इस समूह के सदस्यों के फायदे की बात करें तो उन्हें हर महीने लगभग 6 से 7 हजार रूपये तक मिल रहे हैं.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बदलाव, जल्द करें ई-केवाईसी अपडेट

किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. खबरों के मुताबिक पीएम किसान की 13वीं किस्त होली से पहले जारी हो सकती है. लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने पीएम किसान के नियमों में कुछ अहम बदलाव किये हैं.

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर है. जहां योजना की 13वीं किस्त होली से पहले जारी की जा सकती है. हालांकि अब तक केंद्र सरकार की तरफ कोई ओपचारिक घोषणा नहीं की गयी है. लेकिन इससे पहले सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़े नियमों में बदलाव किये हैं.

बता दें कि, योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए अब ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है. अगर वो अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाएंगे तो उन्हें 13वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से उनके खाते में दो हजार रुपये भी ट्रांसफर नहीं किये जाएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो देश में लाखों किसानों से अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं अपडेट करवाया है. जिस वजह से हो सकता है कि, ये किसान योजना से वंचित हो जाएं.

तुरंत कराएं ई-केवाईसी अपडेट

जिन भी किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाय है. उनके लिए बड़ी समस्या हो सकती है. इससे बचने के लिए किसान भाई अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर कृषि विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं. जहां पर आसानी से उनका ई-केवाईसी अपडेट हो जाएगा. इसके अलावा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर कृषि विभाग की तरफ से जारी किया गया है.

यहां से मिलेगी सारी जानकारी

155261 या 1800115526 और 011-23381092 पर किसान भाई कॉल करके सारी जानकारियां ले सकते हैं. ये नंबर पूरी तरह से टोल फ्री हैं. इसके अलावा PMKISAN-ICT@GOV.IN पर विजिट करके इससे जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती है. केंद्र सरकार ने अपनी 12वीं किस्त पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी की थी. जिसके लिए 16 हजार करोड़ रुपयों का खर्चा किया गया था. वहीं इस किस्त का फायदा करीब 8 करोड़ किसनों को मिला था.

घर बैठे लिस्ट में चेक करें स्टेटस

पीएम किसान की लिस्ट में अगर कोई किसान अपना स्टेट्स चेक करना चाहता है तो, वो ये काम घर बैठे भी कर सकते हैं. जिसके लिए उन्हें सबसे पहले पीएम किसान कि ऑफिशियल वेब साइट PMKISAN-ICT@GOV.IN पर विजिट करना होगा. जिसके होम पेज के दाहिनी तरफ लाभार्थी स्थिति टैब पर क्लिक करना पड़ेगा. जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा. जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना होगा. इसके बाद कैप्चा कोड लिखते ही आपको अपनी पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएगी.

•

राजस्थान सरकार ने चलाई छात्रा प्रोत्साहन योजना, मिलेगा 40 हजार का अनुदान

हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है. इस वजह से इसका औधा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है. देश का ये स्थान हमेशा कायम रहे, इसके लिए सरकार भी कृषि से जुड़ी कई योजनाओं को धरातल पर उतार रही है.

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई तरह के लोन, सब्सिडी और बीमे का इंतजाम कर रखा है. किसान परिवारों की आय के साथ खुशहाली बढ़े, इस ओर भी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं. लेकिन देश का भविष्य यानि की युवा वर्ग को सरकार इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. सरकार का ध्यान खासतौर पर उन किसान परिवारों की तरफ ज्यादा है, जो खेती किसानी के सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं. जिनकी पढ़ाई के लिए स्कालरशिप का प्रावधान किया है. जिसे देखते हुए अब राजस्थान सरकार ने छात्रा प्रोत्साहन योजना चलाई हैं. जिसे लेकर बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान भी दिया जा रहा है.

जानिए क्या है छात्रा प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अपना बजट पेश किया. जिसमें सरकार ने छात्रा प्रोत्सहन योजना की सहायता राशि को बढ़ा दिया है. ऐसे में जिन भी बेटियों को कृषि के क्षेत्र में रूचि है, उनके लिए एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा.
अब तक छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा की बेटियों को एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी. लेकिन राजस्थान ने अपने आम बजट में 5 हजार की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 15 हजार रूपये कर दी गयी है.

जानिए कितना कितना बढ़ा अनुदान

- एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जहां 12 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, वहीं इस अब राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है.
- एग्रीकल्चर में पीएचडी करने वाली छात्राओं को अब तक 15 हजार रुपये का अनुदान मिलता था, जिसे बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया है.
- एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ यह अनुदान हर साल दिया जाता है. लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने अपने आम बजट में इजाफा करते हुए कुल 50 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया है.

हालांकि राजस्थान सरकार की छात्रा प्रोत्साहन योजना का फायदा एग्रीकल्चर की स्टडी करने वाली हर बेटी ले सकती है. लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ योग्यता भी निर्धारित की है. ये योग्यता की है, चलिए जान लेते हैं.

- इस स्कीम में आवेदन करने वाली छात्रा का मूल निवास राजस्थान होना जरूरी है.
- जो छात्राएं राजस्थान के गांव या शहर में रहती हैं, वो सभी इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
- आवेदन करने वाली छात्राओं का बैंक में अकाउंट होना जरूरी है.

क्या होने चाहिए दस्तावेज?

- छात्रा जा आधार कार्ड होना जरूरी है.
- छात्रा का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- छात्रा के पास लास्ट क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए.
- आवेदक छात्रा के पास संस्था प्रधान का ई साइन प्रमाण पत्र होना चाहिए.
- छात्राओं के पास रेगुलर स्टूडेंट संस्था का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

ऐसे करें अप्लाई

रजस्थान की रहने वाली बेटियां जो एग्रीकल्चर सेक्टर की पढ़ाई करना चाहती हैं, वो सभी छात्राएं सरकार की छात्रा प्रोत्साहन स्किन का फायदा ले सकती हैं. इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार के ऑफिशियल पोर्टल राज किसान साथी पर जाना होगा. इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके ई मित्र केंद्र के जरिये भी अप्लाई कर सकते हैं

कृषि सेक्टर में होगी बंपर कमाई, छात्रों को मिलेगी नौकरी

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि को बेहतर और बेहतर बनाने को लेकर कई योजनाओं पर सरकारें काम करने में लगी हुई हैं. इसी तर्ज पर कृषि सेक्टर पर सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है.

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंचे. जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह राष्ट्रिय कृषि विप विपणन संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का चतुर्थ दीक्षांत समारोह एवं एग्री इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के उदघाटन कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि, देश में कृषि के सेक्टर को गांवों में ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए वो छात्र अपना योगदान दें, जो कृषि से जुड़े हुए हैं.

तोमर ने ये भी कहा कि, संस्थान में 60 सीटें और बढ़ाने और छात्रावास में रहने की बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि, कृषि का सेक्टर सबसे जरूरी है और अहम है. जिसमें सबका इंटरेस्ट बढ़े. ताकि युवा भी इसके प्रति आर्षित हों. इतना ही नहीं तोमर ने कहा कि, ये हम सब की जिम्मेदारी भी है. कृषि सेक्टर में लोगों के लिए बंपर रोजगार है, लेकिन इसमें किसानों की देशभक्ति भी झलकती है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कृषि में उत्पादन के बिना बिलकुल काम नहीं चल सकता.

चुनौतियों का कर रहें सामना

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरने कहा कि, कृषि के सेक्टर में अनगिनत चुनौतियां हैं. जिसको हल करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है. फसलों का विविधीकरण, उपज की बिक्री में बिचौलियों का खात्मा, और महंगी फसलों की तरफ बढ़ने जैसी चुनौतियों से योजना के अनुसार निपटा जा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि, साइंटिस्ट ने कृषि सेक्टर में काफी मेहनत की है. बात किसानों की करें तो उनकी कठिन मेहनत और सरकार की किसानों के हित में बनाई गयी नीतियों की वजह से कृषि में प्रगति हुई है. ज्यादातर उत्पादकों मके मामले में देश पूरी दुनिया में पहले या दूसरे पायदान में खड़ा है. जिसे मिलकर और भी आगे बढ़ाना है.

देश से खाद्यान को लेकर अपेक्षाएं

केंद्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, पूरी दुनिया को हमारे देश से खाद्यान को लेकर काफी सारी अपेक्षाएं हैं. जिसे पूरा किया जा रहा है, और आगे भी किया जाता रहेगा. किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की कोशिशों में अब तक कोई कमी नहीं आई है. आजीविका सही ढंग से चलती रहे, इसके लिए नौकरी करनी बेहद जरूरी है. लेकिन कृषि के सकते को पहले से बेहतर बनाना भी जरूरी है, क्योंकि देश की करीब 56 फीसद आबादी इसी पर निर्भर है.

देश के सुनहरे भविष्य के लिए लागू हो रहीं योजनाएं

तोमर ने कहा कि, देश के प्रधानमंत्री हमेशा से ही इस बात पर जोर देते हैं कि, हम अपना आज खूबसूरत तो बनाएंगे ही, लेकिन देश की आजादी के अमृत काल तक भारत को एक विकसित राष्ट्र भी बनाना है. क्योंकि यह अवसर देश के लिए ना सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि सुनहरा भी है. जिसका फायदा उठाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के कंधों पर है. साल 2047 तक देश के भविष्य ऐसा ही होगा, कि वो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेगा. जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रमों के साथ साथ योजनाएं लागू की जा रही हैं.

विश्व गुरु बनेगा भारत

मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि, कल का इंतजार करना मतलब खुद के साथ बईमानी करने जैसा है. जो भी करना है, उसे आज ही करना उचित है. हालांकि देश में एग्रीकल्चर स्टार्टअप ने काफी अच्छे और सफल प्रयोग किये हैं. साल 2014 में जब सरकार बनी थी, तब सभी सेक्टर से कुल 32 स्टार्टअप थे. जिन्हें पीएम ने लगातार प्रोत्साहित किया. लेकिन आज अन्य सेक्टर को मिलाकर बात की जाए तो करीब 10 हजार से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं. इन सभ की ताकत को मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा होगा.

स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स किये लांच

कार्यक्रम में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट के छात्रों को डिप्लोमा बांटा. इसके आलवा मेधावी छात्रों को पदक भी दिए. साथ ही उन्होंने नियाम से प्रशिक्षित और अनुदानित स्टार्टअप के प्रोडक्ट भी लांच किये. और इससे जुड़े अनुदान चेक भी बांटे.

ऐसे करें खीरे की खेती, मिलेगा मुनाफा ही मुनाफा

गर्मियों के मौसम में लोगों को खीरा सबसे ज्यादा पसंद आता है. इससे ना सिर्फ प्यास बुझती है, बल्कि यह शरीर को अंदर से तरोताजा कर देता है. खीरे से हेल्थ को बहुत फायदा होता है, साथ ही यह स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अनगिनत गुणों वाले खीरे की खास तरह से खेती करके किसान भाई मुनाफा ही मुनाफा कमा सकते हैं.

बात जब खीरे की खेती करने की आती है तो इसकी खेती खरीफ और जायद दो सीजन में सबसे ज्यादा की जाती है. इसके अलावा खीरे की खेती ग्रीन हाउस में पूरे साल भर बड़ी ही आसानी के साथ की जा सकती है. हालांकि खीरे की डिमांड बसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में होती है. क्योंकि इसकी तासीर काफी ठंडी होती है. इस वजह से इसका सेवन गर्मियों में सबसे ज्यादा किया जाता है. गर्मियों में खीरा खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रहती हैं. खीरे में 95 प्रतिशत पानी होता है जो गर्मियों में शरीर को डी-हाईड्रेट होने से बचाता है. खीरे में कई तरह के विटामिन मौजूद होते हैं जो स्किन और बालों के लिए काफी अच्छे होते हैं. सलाद, सब्जी या फिर कच्चा किसी भी तरह से खीरे का सेवन किया जा सकता है.

खीरे से जुड़ी खास जानकारी

खीरे का नाम कुकुमिस स्टीव्स है. इसे खास रूप से भारत में उगाया जाता है. खीरे की बेल होती है, जिसमें इसके फल लटकते हैं. खीरे के बीजों का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए भी किया जा सकता है. जो शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही काफी अच्छा होता है. खीरे के पौधे का आकार लंबा और इसके फूल पीले रंग के होते हैं. खीरे का इस्तेमाल स्किन, किडनी और दिल से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है.

क्या हैं खीरे की उन्नत किस्में?

भारतीय किस्में

स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूना खीरा, कल्यानपुर मध्यम, खीर 90, पूसा खीरे जैसी करीब 75 किस्में हैं.

नवीनतम किस्में

स्वर्ण शीतल, पूसा उदय, स्वर्ण पूर्णा आदि.
ये भी देखें: खीरा की यह किस्म जिससे किसान सालों तक कम लागत में भी उपजा पाएंगे खीरा

संकर किस्में

पंत संकर खीरा, प्रिया, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2 आदि.

विदेशी किस्में

जापानी लौंग ग्रीन, स्ट्रेट 8, पोइनसेट आदि.
खीरे की खेती के लिए क्या हो जलवायु और मिट्टी?

खीरे की उन्नत खेती के लिए रेतीली दोमट और भारी मिट्टी में उगाया जाता है. इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई और दोमट मिट्टी दोनों की जरूरत होती है. खीरे की अच्छी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मां कम से कम 5 से 7 के बीच में होना चाहिए. अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए अच्छे तापमान की जरूरत होती है.

क्या है खेती का सही समय?

खीरे की खेती पाले से खराब हो सकती है. इसलिए इसकी खेती के लिए जायद सीजन सबसे अच्छा होता है. गर्मियों के मौसम में खेती के बीजों की बुवाई फरवरी और मार्च के महीने में होती है. बारिश के मौसम में इसकी बुवाई जून से जुलाई में की जाती है. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बुवाई मार्च और अप्रैल के महीने में की जाती है.

कैसे करें जमीन तैयार?

खीरे की खेती करने से पहले जमीन को अच्छे से तैयार करना बेहद जरूरी है. इसके लिए पहली जुताई मिट्टी को पलटने वाले हल से करके इसकी दो से तीन बार जुताई देसी हल से करनी चाहिए.
ये भी देखें: भूमि विकास, जुताई और बीज बोने की तैयारी के लिए उपकरण

कितनी हो बीज की सही मात्रा?

अगर किसी किसान का खेत एक एकड़ है तो उसके लिए कम से कम एक किलो खीरे के बीजों की मात्रा काफी है. इस बात का ध्यान रखें कि, बिजाई से पहले फसल को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिए जरूरी उपचार करें. बुवाई से पहले बीजों का कम से कम दो से तीन ग्राम कप्तान के साथ उपचार किया जाना चाहिए. इसके बीज बोने के लिए ढ़ाई मीटर चौड़े बैड का चुनाव करें. हर जगह दो बीजों की बुवाई करें औए उनके बीच कम से कम 50 से 60 सेमी. का फासला जरूर रखें.

कैसा हो बुवाई का सही ढ़ंग?

खीरे के बीजों की बुवाई छोटी सुरंग विधि से की जा सकती है. इस विधि से खीरे की पैदावार जल्दी होती है. इसके लिए गड्ढे को खोदकर बुवाई करनी चाहिए. इसके साथ ही खालियां बनाकर बुवाई और गोलाकार गड्ढे खोदकर भी बुवाई की जा सकती है.

कितनी हो खाद की मात्रा?

खीरे की खेती से पहले खेत तैयार करते वक्त 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटेशियम को शुरुआत में खाद के तौर पर डालें. बुवाई के समय नाइट्रोजन का एक तिहाई हिस्सा और पोटेशियम और सिंगल सुपर फास्फेट को मिलाकर डालें. बुवाई के लगभग एक महीने के बाद बची हुई खाद का भी इस्तेमाल कर लें.

कैसे करें खरपतवार को नियंत्रित?

खीरे की खेती के दौरान हो रही खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए गोड़ाई और रसायनों की मदद ली जा सकती है. इसके अलावा आधा लीटर ग्लाइफोसेट को हर 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है. इसका छिड़काव मुक्य फसल पर ना करें.

कैसे करें सिंचाई?

खीरे की खेती गर्मियों के मौसम में की गयी है, तो इसकी सिंचाई बार बार की जानी चाहिए. हालांकि बारिश के मौसम में इसे सिंचाई की जरूरत नहीं होती. इसमें बुवाई से पहले एक बार सिंचाई की जानी चाहिए. जिसके बाद तीन से चार दिनों के गैप पर सिंचाई की जाती है. वहीं दूसरी बुवाई के बाद 5 से 6 दिनों पर सिंचाई की जाती है.

कैसे करें पौधे की देखभाल, बिमारी और रोकथाम

एन्थ्राक्नोस नाम की बिमारी में फल गलने लगते हैं. यह बिमारी खीरे के सारे हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित करती है. खासतौर से वो हिस्से जो जमीन के ऊपर होते हैं. इसमें पुराने पत्तों पर पीले रंग के दाग धब्बे और फलों पे गहरे गोल धब्बे नजर आते हैं. इस बिमारी की रोकथाम के लिए क्लोरोथैलोनिल और बेनोमाइल का इस्तेमाल किया जाता है.

अगर पौधा मुरझाए

इर्विनिया नाम की इस बिमारी से पौधे की नाड़ी प्रभावित होने लगती है. जिस वजह से पौधा मुरझा या सूख जाता है. पौधे को इस बीमारी से बचाने के लिए कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

पत्तों में दिखे सफेद धब्बे

अगर आपको पत्तों के ऊपर पाउडर वाले सफ़ेद धब्बे नजर आएं, तो सतर्क होने की जरूरत है. इससे पौधों को बचाने के लिए बैनोमाइल या क्लोरोथैलोनिल का स्प्रे किया जा सकता है.
अगर हो जाए चितकबरा रोग
अगर पौधे को चितकबरा रोग जाए तो पौधों का विकास रुक जाता है. इसके अलावा पत्ते मुरझा जाते हैं और निचले हिस्से में पीलापन हो जाता है. इसकी रोकथाम के लिए डियाजीनॉन का स्प्रे किया जाता है.

अगर लग जाए फल की मक्खी

खीरे की फसल में लगने वाला यह बेहद गंभीर रोग है. इसमें फल गलने शुरू हो जाते हैं और टूटकर नीचे गिर जाते हैं. इसकी रोकथाम के लिए पत्तों पर नीम के तेल का स्प्रे किया जाना चाहिए.
कैसे करें फसल की कटाई?
बुवाई के करीब एक से डेढ़ महीने में पौधे में फल लगाना शुरू हो जाते हैं. खीरे की कटाई खास तौर पर बीज के नरम होने, फल छोटे और हरे होने पर करें. इसकी कटाई के लिए धारदार चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करें. इसकी पैदावार प्रति एकड़ 33 से 42 क्विंटल तक होती है.

कैसा हो बीज का उत्पादन

खीरे के उत्पादन के लिए भूरे रंग के बीज अच्छे होते हैं. बीज निकालने के लिए फलों के गुदे को कम दे कम दो दिनों तक पानी में रखें, ताकि बीज आसानी से अलग किये जा सकें. उसके बाद उन्हें हाथों से जोर से रगड़ा जाता है. जो बीज पानी में भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, उनका इस्तेमाल कई और कामों में किया जाता है.

इस तरह से खीरे की खेती करने से किसान भाइयों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है.

पैक्स और डेयरी से जुड़े सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर बढ़ जाएगी किसानों की आमदनी

हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान से यह बात सामने आई है कि भारत में सरकार सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती देने के लिए कार्य कर रही है. सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर इसे मजबूत बनाने के लिए कई तरह की सहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा.

खबरों की मानें तो देश में एक बार फिर से सहकारिता आंदोलन जोर पकड़ने वाला है. केंद्र सरकार भी इसे लेकर बड़े लेवल पर काम कर रही है. इसके तहत अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स; PACS), डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गठित की जाएगी. इस सभी कार्य को लेकर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है.

हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक मंत्रिमंडलीय बैठक में इस फैसले की जानकारी जनता को दी है. अभी भी पूरे देश में लगभग 63,000 पैक्स समितियां कार्य कर रही है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी से पता चला है कि देश में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में कई तरह की समितियों का गठन किया जाएगा.

जलाशय पंचायत में बनाई जाएंगी मत्स्य पालन समिति

इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में पैक्स समिति तो बनाई ही जाएगी इसके अलावा सभी पंचायत जहां जलाशय है वहां पर मत्स्य पालन समिति बनाने की योजना भी बनाई जा रही है. अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह जानकारी दी है कि इस योजना के प्रस्ताव को हाल ही में चल रही बाकी सभी सरकारी योजनाओं के साथ मेल मिलाप करते हुए लागू किया जाएगा.

यह सहकारी समितियां योजना को एक जरूरी और आधारभूत ढांचा बनाने में मदद करेगी और आगे चलकर यह इस योजना को एक सशक्त रूप देने में भी काफी सहायक साबित होगी.

कंप्यूटरीकरण के लिए रखा गया है बजट

इस योजना के तहत जो भी किसान सहकारी समिति के सदस्य बनते हैं उन्हें खरीद और विपणन जैसी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाएंगी जो उनकी आमदनी बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करेगी.इन सभी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे जो वहां के लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाले हैं.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई समिति के साथ मिलकर इन सभी पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण करने की बात भी कही है. अगर यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाती है तो ना सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता आएगी बल्कि सभी जुड़े हुए व्यक्ति सही तौर पर जवाबदेह होकर अपना काम कर सकते हैं.हाल ही में देश भर में एक्टिव करीब 63,000 पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और इसमें से केंद्र की हिस्सेदारी लगभग 1,528 करोड़ रुपये की मानी जा रही है..

बाजार में मिलावटखोर लाल मिर्च में कर रहे मिलावट ऐसे करें मिलावटयुक्त मिर्च की जाँच

बाजार में मिलावटखोर लाल मिर्च में कर रहे मिलावट ऐसे करें मिलावटयुक्त मिर्च की जाँच

आज हम आपको लाल मिर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप यह पहचान सकें कि कौन सी मिर्च शुद्ध है और कौन सी मिटावती। क्योंकि लाल मिर्च को अच्छी तरह जांच परखने के उपरांत ही प्रयोग करना चाहिए। कुछ मिलावट खोर लाल मिर्च में डाई अथवा नकली लाल रंग का मिश्रण करके बेचते हैं। जो कि आपकी सेहत को काफी प्रभावित करता है। बहुत सारे तरीकों से लाल मिर्च की शुद्धता और इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। खाने को स्वादिष्ट बनाने में लाल मिर्च की अपनी अहम भूमिका होती है।

लाल मिर्च के तड़के के बिना सब्जी में मजा नहीं आता है, भारत में रहने वाले लोग बिना तड़का लगाए सब्जी चाव से नहीं खाते हैं। इसलिए लाल मिर्च भारतीय भोजन के व्यंजनों की जान मानी जाती है। इतना ही नहीं देसी लाल मिर्च के तीखेपन का चस्का वर्तमान में विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इसलिए आजकल लालमिर्च विदेश में भी खूब निर्यात होने वाले मसालों में लाल मिर्च का नाम भी शम्मिलित है। अत्यधिक मांग होने की वजह से बाजार में लाल मिर्च की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जिसका व्यापारी गलत लाभ उठाते हैं एवं लाल मिर्च के अंदर डाई, ईंट का पाउडर, गेरुआ, लाल रंग इत्यादि का मिश्रण कर देते हैं।

जो कि एक कानूनन अपराध होता है, परंतु इसके अलावा भी लाल मिर्च में मिलावट होने की खबर सामने आती रहती हैं। अगर आप स्वयं तथा स्वयं के परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो लाल मिर्च को उपयोग में लाने से पूर्व उसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता की जाँच पड़ताल अवश्य करलें। क्योंकि अगर आपने भूल से भी नकली लाल मिर्च का उपभोग किया तो आपके पेट से लेकर आँतों तक की स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं।

ईंट के पाउडर-गेरुआ की मिलावट की कैसे जाँच करें
मिर्च का रंग ईंट-गेरुआ का रंग दोनों लाल व एक जैसे होते हैं। इसी बात का फायदा उठा कर मिलावट खोर लाल मिर्च में ऐसे हानिकारक पदार्थों की मिलावट कर देते हैं। आप जिस मिर्च का उपयोग कर रहे हैं तो याद रहे उसमें भी यह नुकसानदायक पदार्थ मिले हो सकते हैं। इसकी जांच पड़ताल करना काफी आसान माना जाता है।

इस ईंट के पाउडर-गेरुआ की मिलावट की जाँच पड़ताल के लिए एक गिलास जल लेकर उसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर देखें। जैसे ही आप जल में मिलाओगे आपको मिट्टी की गंध का आभाष होने लगेगा जाएगी। साथ ही, पानी का रंग भी परिवर्तित होने लग जाएगा।

इसका पता लगाने की एक और विधि है, जिसके अंतर्गत लाल मिर्च का पाउडर लेकर उसके ऊपर गिलास को घिसेंगे। उस स्थिति में यदि आपको किरकिरापन का आभाष हो तो मान लीजिए कि लाल मिर्च में मिलावटयुक्त होने की आशंका है।

डाई अथवा आर्टिफिशियल (ARTIFICIAL) रंग की मिलावट की कैसे जाँच करें

लाल मिर्च में आमतौर पर डाई और आर्टिफिशियल रंग की मिलावट के बारे में भी बहुत सी बात सामने आएंगी। हालांकि, ब्रांडेड लाल मिर्च में इस प्रकार की खबर नहीं सुनी है। परंतु, खुले रूप से बिकने वाले लाल मिर्च पाउडर में डाई अथवा आर्टिफिशियल रंग मिले होने के अधिक होते हैं।
इसकी जाँच पड़ताल करने हेतु एक गिलास जल में एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर का उचित प्रकार से मिश्रण कर लें। अगर लाल मिर्च को बेहतर ढंग से घोला जाए एवं पानी का रंग गहरा लाल हो जाए तब जान लें कि लाल मिर्च मिलावटयुक्त है। क्योंकि लाल मिर्च को जल में नहीं घोल सकते हैं। यह जल के ऊपर भाग पर ही तैरती रहती है।

लाल मिर्च पाउडर में स्टार्च की मिलावट का कैसे पता लगाएं

हम जब कभी भी लाल मिर्च में स्टार्च की मिलावट के बारे में सुनते हैं। उस स्थिति में हमको जागरुकता एवं सावधानी से शुद्धता की जाँच पड़ताल अवश्य करनी चाहिए। अगर आप भी खरीदकर लाए लाल मिर्च पाउडर में स्टार्च की मिलावट के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो इसकी जाँच करने हेतु आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर कटोरी में डालें एवं इसमें टिंचर आयोडीन अथवा आयोडीन SOLUTION की कुछ बूंदें मिलाएं। वर्तमान में अगर लाल मिर्च पाउडर का रंग नीला होने की स्थिति में है तो स्टार्च की मिलावट जरूर हुई है, उसको खाने के बाद ही आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है।

FSSAI द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं

मिलावटयुक्त लाल मिर्च के बारे में सूचना लोगों तक मुहैय्या कराने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बहुत सी कोशिश में लगा रहता है। एक जागरुकता अभियान के दौरान यह व्यक्त किया गया। कैसे लाल मिर्च में चाक पाउडर, चोकर, साबुन, लाल तेल, ईंट का चूरा, पुरानी और खराब मिर्च आदि मिलायी जाती है। इसको खाने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसका सेवन करने से पूर्व लाल मिर्च की शुद्धता की जाँच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए।

खुशखबरी: इस राज्य में आवारा पशुओं से परेशान किसानों को मिलेगी राहत

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान करदी है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को आवारा पशुओं द्वारा मचाई जा रही तबाही से राहत प्रदान करने हेतु 1,500 ग्राम पंचायतों में गौशाला एवं आश्रय निर्मित किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में छुट्टा घूमने वाले गौवंशों की संख्या में बढ़वार देखने को मिल रही है। इन दुधारू पशुओं से जब पशुपालकों को दूध की प्राप्ति नहीं होती तो इनको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में यह पशु सड़कों को ही अपना घर मान लेती हैं। जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबर सुनने को मिलती हैं।

साथ ही, इनके खाने के लिए चारे की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से ये पशु खेतों में घुंसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। जो कि किसानों के लिए ही चुनौती उत्पन्न करती है। राजस्थान, यूपी और बिहार में आवारा गौवंशों की परेशानियों में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। इन तीनों प्रदेशों की राज्य सरकारें स्वयं के स्तर पर इस चुनौती से निपटने हेतु कार्य कर रही हैं।

इसी क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी राजस्थान सरकार ने भी अहम निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ग्राम पंचायतों के अंतर्गत पशु आश्रय स्थल एवं गौशालाओं के निर्माण की घोषणा करदी है। इस कार्य को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के चलते किया जाना है।

गौशाला/पशु आश्रय स्थल बनाने की क्या रणनीति है

राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना को मंजूरी देदी है। इसके प्रथम चरण में 1,500 ग्राम पंचायतों में गौशालाएँ व पशु आश्रय स्थल बनेंगे, इसके लिए 1,377 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता से पशुओं हेतु आश्रय स्थल निर्मित किए जाने हैं। जहां इनको चलाने हेतु बेहतर कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत, स्वयं सेवी संस्था उपस्थित रहेगी। राज्य इन इन ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण हेतु एक-एक करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया जाना है । इस योजना के अनुसार, 90% फीसद धनराशि को राज्य सरकार एवं 10% फीसद धनराशि को कार्यकारी एजेंसी द्वारा वहन किया जाना है। फिलहाल, इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपये के खर्च से 200 एवं वर्ष 2023-24 में 1,193.40 करोड़ रुपये के खर्च से 1,300 ग्राम पंचायतों में गौशालाऐं बनायी जा रहा है।

किसानों को छुट्टा पशुओं से मिलेगी राहत

आवारा पशुओं की तादात में वृद्धि का सर्वाधिक नुकसान किसानों को ही तो भोगना होता है। यह आवारा पशु खेतों में जाकर के फसलों को खा जाते हैं। फसल का उत्पादन प्राप्त होने से पूर्व ही किसानों के सारा खेत पशु खाकर साफ कर देते हैं। इस प्रकार पूरे सीजन अथक प्रयास और परिश्रम करने वाले किसानों को केवल निराशा और हताशा ही प्राप्त होती है। आवारा पशुओं द्वारा बहुत बार किसानों को उस हद तक हानि हो जाती है। जिसका मुआवजा तक किसानों को मिलना काफी कठिन सा हो जाता है, जिस की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु, अब राजस्थान के किसानों की इस परेशानी का निराकरण तो निकलेगा ही, साथ ही, छुट्टा एवं निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थल भी मुहैय्या हो पाएगा।

किसानों को छुट्टा पशुओं से मिलेगी राहत

आवारा पशुओं की तादात में वृद्धि का सर्वाधिक नुकसान किसानों को ही तो भोगना होता है। यह आवारा पशु खेतों में जाकर के फसलों को खा जाते हैं। फसल का उत्पादन प्राप्त होने से पूर्व ही किसानों के सारा खेत पशु खाकर साफ कर देते हैं। इस प्रकार पूरे सीजन अथक प्रयास और परिश्रम करने वाले किसानों को केवल निराशा और हताशा ही प्राप्त होती है। आवारा पशुओं द्वारा बहुत बार किसानों को उस हद तक हानि हो जाती है। जिसका मुआवजा तक किसानों को मिलना काफी कठिन सा हो जाता है, जिस की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। परंतु, अब राजस्थान के किसानों की इस परेशानी का निराकरण तो निकलेगा ही, साथ ही, छुट्टा एवं निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थल भी मुहैय्या हो पाएगा।

इस राज्य में सबसे ज्यादा किसान कर रहे हैं आत्महत्या, जाने क्या है कारण

एक बार फसल लगाने के बाद किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखा और बहुत ज्यादा बारिश उनमें से एक हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने से कभी-कभी खेतों में खड़ी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जो किसानों के ऊपर भारी कर्ज और परेशानी छोड़ देता है।

पिछले साल बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। इससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, ऐसे में किसान कर्ज में डूब गए। मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो साल 2022 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लगभग 1000 से ज्यादा किसानों ने इन समस्याओं के चलते आत्महत्या की है। यह आंकड़े बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। कार्यालय के अधिकारियों की मानें तो इससे पिछले साल की गई आत्महत्या 887 थी जो इस साल बढ़कर 1023 हो गई हैं। किसानों की आत्महत्या एक ऐसा आंकड़ा है, जो कोई भी सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है।

मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो साल 2001 और साल 2010 के बीच हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से बहुत से रिपोर्ट मीडिया में दर्ज भी नहीं होती है। यह आंकड़े ना सिर्फ चौकाने वाले हैं बल्कि दुखदाई भी हैं। एक बार फसल बर्बाद हो जाने के बाद किसानों के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वह मौत को गले लगाना ही सबसे सही समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में कुछ वर्षों में सूखे जैसी स्थिति और अन्य में अत्यधिक बारिश देखी गई है, जिसने फसल उत्पादकों की कठिनाइयों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई नेटवर्क का भी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

एक बार फसल लगाने के बाद किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखा और बहुत ज्यादा बारिश उनमें से एक हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने से कभी-कभी खेतों में खड़ी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जो किसानों के ऊपर भारी कर्ज और परेशानी छोड़ देता है।

पिछले साल बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। इससे खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, ऐसे में किसान कर्ज में डूब गए। मीडिया की रिपोर्ट की मानें तो साल 2022 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में लगभग 1000 से ज्यादा किसानों ने इन समस्याओं के चलते आत्महत्या की है। यह आंकड़े बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। कार्यालय के अधिकारियों की मानें तो इससे पिछले साल की गई आत्महत्या 887 थी जो इस साल बढ़कर 1023 हो गई हैं। किसानों की आत्महत्या एक ऐसा आंकड़ा है, जो कोई भी सरकार बढ़ाना नहीं चाहती है।

किसानों को अपनी उपज का अच्छा रिटर्न मिलना है जरूरी

संख्या पर अंकुश लगाने की नीतियों पर हेगाना ने कहा कि इन नीतियों में खामियां ढूंढना और उन्हें बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही जरूरी है, कि कुछ ऐसे लोगों का समूह बनाया जा सके जो इस पर काफी एक्टिव हो कर काम करें। संपर्क किए जाने पर, महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि हालांकि किसानों के लिए कई बार कर्जमाफी हुई है। लेकिन आंकड़े (आत्महत्या के) बढ़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया में कहा कि केवल किसानों का कर्ज माफ कर देना ही काफी नहीं है।

हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा खासा रिटर्न मिले। जब किसान फसल लगाते हैं, तो उस पर काफी तरह का खर्चा करते हैं। अगर वह खर्चा ही ना निकाल पाए तो यह उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन कर सामने आता है। दानवे ने बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे घटिया किस्म के बीज और खाद के बारे में भी बात की और इस पर चिंता व्यक्त की है। अगर किसानों को सही तरह के बीज और खाद ही नहीं मिल पाएंगे तो उत्पादन को बढ़ाना मुश्किल है।

इस देश में प्याज की कीमतों ने आम जनता के होश उड़ा दिए हैं

प्याज बागवानी के अंतर्गत अत्यधिक खपत होने वाली सब्जी है। जिसके मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। भारत में जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं, तो लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। फिलहाल फिलीपींस (PHILIPPINES) की भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि फिलीपींस में प्याज के भावों ने तबाही मचा रखी है। वहां प्याज भारतीय करेंसी की तुलना में 900 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है।

बागवानी फसलें जैसे कि भावों को संतुलन में रखना बेहद आवश्यक होता है। इनके भाव बढ़ने से आम जनता की रसोई का बजट खराब हो जाता है। साथ ही, सरकार के ऊपर भी भाव को संतुलन में लाने के लिए दबाव बनने लगता है। इस मुद्दे पर विपक्ष भी सक्रियता से सरकार को घेरता है। अगर निरंतर भावों में बढ़ोत्तरी देखने को मिले तो आम जनता भी खिलाफ में सड़कों पर उतर आती है। आजकल फिलीपींस की भी यही दसा देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि यहाँ प्याज की कीमत में बेहद ऊंचाई पकड़ली है। वहाँ के देशवासियों की हालत दूभर हो गई है। आम जनता सरकार से भावों को नियंत्रण में लाने के लिए गुहार कर रही है।

फिलीपींस में प्याज के भाव ने लोगों को चिंतित कर दिया है
फिलीपींस में प्याज के भाव सातवें आसमान पर हैं। खबरों के मुताबिक, वहां प्याज का मूल्य 11 डॉलर पर टिकी हुई है। भारतीय करेंसी की तुलना में इसका मूल्य 900 रुपये के आसपास है। वर्तमान में भारत के बाजारों में सेब 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इस परिस्थिति में फिलीपींस के एक किलो प्याज के भाव में 10 किलोग्राम सेब खरीदे जा सकते हैं।

फिलीपींस मार्च तक हजारों टन प्याज आयात करेगा
वर्तमान में प्याज के बढ़ते दामों की वजह से फिलीपींस सरकार भी काफी दबाव में है। प्याज की घरेलू उपभोग की आपूर्ति के लिए जनता द्वारा सरकार से निरंतर मांग की जा रही है। फिलीपींस सरकार ने इसको गहनता से लिया है। सरकार ने घरेलू खपत सुनिश्चित करने हेतु मार्च तक तकरीबन 22,000 टन प्याज का आयात हेतु घोषणा करदी है। सरकार की घोषणा के बाद आम जनता को उम्मीद और शांति मिली है। परंतु, जनता प्याज आयात हेतु प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करने की गुहार कर रही है।

चीन से तस्करी से आई 153 मिलियन डॉलर की प्याज जब्त

कुछ खबरों के अनुसार फिलीपींस में चीन से प्याज की तस्करी हो रही है। तस्करी-विरोधी प्रयासों की निगरानी करने वाली समिति के प्रमुख कांग्रेस जॉय सालखेडा का कहना है, कि कृषि तस्करी को संतुलन में लाने हेतु भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी नागरिक एवं उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही प्याज की तस्करी की अच्छी तरह जाँच पड़ताल की जाएगी। वर्तमान में फिलीपींस के सीमा शुल्क ब्यूरो द्वारा चीन से तस्करी करके लाई गई 153 मिलियन डालर की लाल व सफेद प्याज को जब्त कर लिया गया है।

जानें पीएम किसान योजना जी 13 वीं किस्त कब तक आएगी

किसानों को पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त की बेहद उत्सुकता से प्रतीक्षा है। किसानों को अनुमान है, शायद इस हफ्ते उनकी 13 वीं किस्त उनके खाते में डाल दी जाएगी। केंद्र सरकार भी 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने हेतु पूर्ण व्यवस्था में लगी हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। किसान वर्तमान में 13 वीं किस्त की प्रतीक्षा में बैठे हैं। आखिर कब तक उनको 13 वीं किस्त मिलेगी। इस बात के लिए किसान सड़कों पर निरंतर बातचीत में लगे हुए हैं। किसानों द्वारा केंद्र सरकार से भी अनुग्रह किया जा रहा है, कि वह इसी माह में शीघ्र से शीघ्र उनके खाते में 13 वीं किस्त ड़ाल दें।

किसानों को कब तक 13 वीं किस्त मिल सकती है

अगर जनवरी माह में 13 वीं किस्त किसानों को कब तक मिलेगी। किसान इस विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, लोहड़ी एवं मकर संक्राति के त्यौहार से पूर्व किस्त किसानों को मिलने की आशा की जा रही थी। परंतु, फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही हैं। उनके मुताबिक तो आने वाले हफ्ते में अथवा जनवरी माह के किसी भी दिन किसानों के खातों में पहुँचा दी जा सकती है। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार निर्धारित समय पर 13 वीं किस्त किसानों के खाते में भेज देगी। दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से किस्त जारी करने के संबंध में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन, इसी हफ्ते अथवा 26 जनवरी से पूर्व किसानों के खातों में उनकी 13 वीं किस्त आने की संभावना है।

किसानों को ऑनलाइन तौर पर इस कार्य को करना अति आवश्यक है

पीएम किसान योजना की आगामी किस्त प्राप्त करने हेतु कृषकों को ई-केवाईसी होनी आवश्यक है। जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना भी बेहद आवश्यक होता है। पंजीयन करते समय राशन कार्ड का सॉफ्ट कार्ड जमा करना होगा। आपको हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको राशन कार्ड की PDF फाइल तैयार कर अपलोड करदें। यदि किसानों ने राशन कार्ड की कॉपी जमा नहीं की तो उस स्थिति में किसान किस्त से वंचित रह जाएंगे।

आधार कार्ड का बैंक खाते से जुड़े रहने की स्थिति में ही मिल पायेगा लाभ

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना बहुत आवश्यक कर दिया है। बैंक से आधार कार्ड जुड़ने की स्थिति में आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, किस्त प्राप्त करने हेतु किसानों का आधार कार्ड बैंक से जुड़ा होना चाहिए। उसके उपरांत ही 13 वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। बतादें, कि अपात्र एवं E-KYC नहीं होने की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 12 वीं किस्त नहीं पहुँच पायी थी। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को ई-केवाईसी कराने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिससे कि वह पीएम किसान योजनासे लाभान्वित हो सकें।

अगर आप भी चावल में मिलावट कर उसे बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए

भारत में उगाए जाने वाले बासमती चावल का पूरी दुनिया में डंका बजता है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो साल 2022-23 में बासमती चावल का निर्यात 24.97 लाख टन दर्ज किया गया है। अमेरिका और यूरोप में तो भारत के बासमती चावल की डिमांड है ही इसके साथ-साथ अरब के देशों में भी भारत से बासमती चावल मंगवाए जाते हैं। यही कारण है, कि पिछले कुछ समय में ना सिर्फ भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। बल्कि हम पूरे विश्व में बहुत ही बड़े स्तर पर चावल का निर्यात भी करते हैं।

भारत की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है, कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजार मानकों के आधार पर खरा उतरने के बाद ही बासमती चावल का निर्यात किया जाए। लेकिन आजकल बहुत से व्यापारी और चावल वितरित करने वाली कंपनियां नकली बासमती चावल बेच रही हैं। इस तरह की गड़बड़ी करते हुए अपनी नोटों से जेबें भर रहे हैं।

ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर अब भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने लगाम कस दी है। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो FSSAI ने बासमती चावल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए खास नियम तय कर दिए हैं, जिनका पालन चावल कंपनियों को करना ही होगा। ये नियम 1 अगस्त 2023 से देशभर में लागू हो जाएंगे। नियमों का पालन न किए जाने पर व्यापारियों और कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

अब बाज़ार में बिकेगा केवल नेचुरल बासमती चावल

असली बासमती चावल में अपनी खुद की एक प्राकृतिक सुगंध होती है। लेकिन आजकल कई कंपनियां आर्टिफिशियल कलर और नकली पॉलिश करते हुए बासमती चावल में बाहर से एक अलग खुशबू डाल देती हैं। इस तरह के नकली चावल देशभर में बेचे जा रहे है। लेकिन अब सरकार ने इस कुकर्म पर लगाम लगाने की ठान ली है। ऐसी कंपनियों पर लगाम कसते हुए अब भारत सरकार के बजट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव) फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2023 नोटिफाई किया गया है।

इसमें बासमती चावल के लिए खास स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, ताकि असली बासमती की पहचान, सुगंध, रंग और बनावट के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। नए नियमों में ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती, पारबॉइल्ड ब्राउन बासमती और मिल्ड पारबॉइल्ड बासमती चावल को प्रमुखता से जोड़ा गया है। इन खास तरह के स्टैंडर्ड का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ सरकार की तरफ से लीगल एक्शन लिया जा सकता है।

किसे कहेंगे असली बासमती चावल

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा निर्धारित रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुसार, असली बासमती चावल वही होगा, जिसमें प्राकृतिक सुगंध होगी। साथ ही, इन नियमों के तहत बासमती चावल को किसी भी तरह से आर्टिफिशियल पॉलिश नहीं किया जाएगा।
जो भी कंपनियां बासमती चावल बेच रही हैं, उन्हें पकने से पहले और पकने के बाद के चावल का आकार निर्धारित करना होगा। इसके अलावा चावल कंपनियों को बासमती चावल में नमी की मात्रा, एमाइलॉज की मात्रा, यूरिक एसिड के साथ-साथ बासमती चावल में टुकड़ों की उपस्थिति और इनकी मात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।

1 अगस्त से लागू हो जाएंगे नियम

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा बासमती चावल के लिए निर्धारित रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों का सबसे बड़ा मकसद बासमती चावल में हो रही मिलावट को खत्म करना है। साथ ही, ग्राहकों के हितों की रक्षा देश नियम के तहत की जाएगी। यहां पर सरकार का मकसद है, कि आपके खाने की थाली में एकदम वैसे ही चावल पहुंच सके जैसा उन्हें उगाया गया है।

इस राज्य के कृषि क्षेत्रफल में हुई वृद्धि भारत के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गयी है

भारत के तेलंगाना राज्य में खेती के दायरे और क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। वर्तमान में रकबे में इजाफा होकर 2.40 करोड़ एकड़ पर पहुँच गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को कृषि से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं का फायदा प्रदान किया जा रहा है। देश में खेती किसानी के विषय में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। देश के प्रत्येक राज्य में फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिल रही है। समस्त राज्य सरकारों का एक ही उद्देश्य है, कि नवीन, उन्नत व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि करने हेतु किसानों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए सरकार किसानों को आर्थिक छूट देकर कृषि यंत्र भी मुहैय्या करा रही हैं। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में भी एग्रीकल्चर क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अधिकारिक आंकड़ों ने राज्यवासियों की खुशी बढ़ा दी है।

भारत के तेलंगाना राज्य के कृषि क्षेत्र में हुई 2.40 करोड़ एकड़ की बढ़ोत्तरी

तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र के अधिकारिक आंकड़े प्रेषित किए हैं। दरअसल, तेलंगाना राज्य पूर्व में आंध्र प्रदेश का भाग था। दीर्घ काल से तेलंगाना राज्य को एक सुरक्षित राज्य निर्मित करने की मांग की जा रही थी। तेलंगाना को 2 जून 2014 को स्वतंत्र तौर पर राज्य बना दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक, तेलंगाना राज्य के गठन के दौरान राज्य का कृषि क्षेत्र 1.31 करोड़ एकड़ था। वर्तमान में प्रदेश का कृषि क्षेत्र बढ़कर के 2.40 करोड़ एकड़ पर पहुँच चुका है। तेलंगाना राज्य निरंतर कृषि क्षेत्र में उन्नति के पथ पर चल रहा है।

तेलंगाना राज्य सरकार ने इस योजना के लिए खर्च किए करोड़ों

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सुदृण और मजबूत करने हेतु लाखों करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य सरकार ने मात्र तीन योजनाओं हेतु अत्यधिक व्यय किया है। आपको बतादें कि रायबंधु, 24 घंटे मुफ्त विघुत एवं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 2.16 लाख करोड़ से ज्यादा व्यय कर एक अद्भुत संरचना का निर्माण किया है। राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं से होने वाले विकास की जानकारी ली जा रही है और मुआयना किया जा रहा है।

तेलंगाना राज्य के अधिकाँश किसानों का खेती की तरफ रुझान

मुख्यमंत्री ने बताया है, कि आजकल खेती किसानी को करना एक कम आय वाले व्यवसाय के रूप में माना जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, यदि कृषि आधुनिक ढंग व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से की जाए तो खेती भी एक अच्छी आय का व्यवसाय होता है। किसान कृषि के माध्यम से काफी मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए अधिकाँश लोगों को कृषि से जुड़ना चाहिए। इससे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। राज्य सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा कि पूर्ण भारतीय किसानों के मन में कृषि क्षेत्र के प्रति जागरूकता एवं दिलचस्पी को बढ़ाना है।

भारत के लिए तेलंगाना प्रेरणा का स्त्रोत

तेलंगाना सरकार खेती किसानी की उन्नति की ओर निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है, कि कृषि क्षेत्र में पुनः दम फूंकने हेतु विभिन्न प्रकार के क्रिया-कलाप जारी कर दिए गए हैं। इनके अंतर्गत डेयरी मवेशियों, हरे फसल वाले खेत, अनाज के ढेर एवं मीठी मृदा की महक वाले तेलंगाना राज्य के गाँव की कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदेश में खेती-किसानी की वृध्दि संपूर्ण भारत हेतु एक आदर्श के रूप में कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए सरकार की तरफ से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी

हम सभी जानते हैं, कि भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले गन्ने से ही सबसे ज्यादा चीनी, गुड़, शक्कर आदि का प्रोडक्शन मिलता है। किसी भी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे उगाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए। यहां के किसान भी इसी तलाश में हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक भी पीछे नहीं रहते हैं और वह अलग-अलग तरह की रिसर्च करते हुए बीज को और उन्नत बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराने की इस समस्या के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। अब किसान चाहें तो घर बैठे ही स्मार्ट किसान एप (SMART GANNA KISAN) या एसजीके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए गन्ना की सीड किट बुक करा सकते हैं। इसके लिए बनाई गई वेबसाइट ENQUIRY.CANEUP.IN पर बीजों का वितरण 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।

गन्ना किसानों को बड़ी राहत

पहले किसानों को गन्ने के उत्पादन के लिए बेहतर बीज जुटाने में बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ता था। समय पर बीज न मिल पाने के कारण बुवाई में देरी हो जाती है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के गन्ना विकास विभाग (CANE DEVELOPMENT DEPARTMENT) को आदेश दिए थे। जिसका अनुपालन करते हुए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गन्ना पर्ची (GANNA PARCHI) की तरह गन्ना सीट बुकिंग की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी है।

हाल ही में गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी द्वारा स्मार्ट गन्ना किसान एसजीके की ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। जिस पर अब किसानों को ऑनलाइन ही सीड बुकिंग की सुविधा मिलेगी। इस तरह किसानों को व्यर्थ की भागदौड़ करने से भी राहत मिलेगी। किसान घर बैठे हैं, अपने फसल के उत्पादन के लिए बीज प्राप्त कर सकते हैं।

लंबी कतारों से मिली मुक्ति और होगी समय की बचत

स्मार्ट गन्ना किसान एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में जानकारी देते हुए संजय भूसरेड्डी बताते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने के लिए भी हासिल करने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। इसके लिए सरकार द्वारा 'मिठास मेले' का आयोजन किया जाता था, जिससे किसानों को काफी परेशानी होती थी।
बहुत बार अगर किसानों को यहां पर पहुंचने में देरी हो जाती थी तो उन्हें बीज नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब बिना कतारों में समय गंवाए किसान घर बैठे ही गन्ना की नई किस्मों की बीजों की बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद किसानों को अपने नजदीकी गन्ना शोध केंद्र से बीज मिल जाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है, कि गन्ना की बीजों की सीड बुकिंग करने के साथ-साथ पेमेंट भी ऑनलाइन किया जाएगा। इस तरह से किसानों के समय की बचत होगी।

कैसे कर सकते हैं गन्ना के नए बीजों की बुकिंग

सबसे पहले किसानों को स्मार्ट गन्ना किसान यानी एसजीके की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। यहां किसान को सबसे पहले कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, जिसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
इस फॉर्म में किसान को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, गांव का नाम, नजदीकी गन्ना शोध केंद्र, गन्ना की किस्म, गन्ना बड संख्या आदि जानकारी देनी होगी। यहां फॉर्म को सबमिट करते ही बीजों की बुकिंग हो जाएगी।

किसानों को मिलेंगी 16 लाख बड सीड किट

उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास विभाग के मुख्य अपर सचिव ने बताया कि किसानों को 9 केंद्रों से करीब 16 लाख की संख्या में बड बीजों की किट (CANE BUD SEED KIT) वितरित की जाएंगी। साथ ही, इस योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए किसान जब चाहें हेल्पलाइन नंबर- 1800-121-3203 या 1800-180-1551 पर भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

भारत ने किया रिकॉर्ड तोड़ चाय का निर्यात

भारत द्वारा रिकॉर्ड तोड़ चाय का निर्यात किया गया है। बीते बहुत से वर्षों में निर्यात के आंकड़े काफी हद तक बढ़े हैं। चाय का विदेशों में किया गया निर्यात इस बार बढ़कर के 18.53 करोड़ किलोग्राम तक पहुँच गया है। दरअसल, ईरान, रूस, यूएई सहित विभिन्न देशों में भारत ने चाय निर्यात की है। कृषि उत्पादों का उत्पादन, निर्यात के संदर्भ में भारत निरंतर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बतादें, कि आलू, गेहूं, धान, गन्ना में भारत की विश्व में एक अलग ही पहचान रखता है। किसानों की मेहनत की वजह से करोड़ों हेक्टेयर में फसलों का उत्पादन किया जाता है। चाय के उत्पादन में भी देश ने अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। मुख्य बात यह है, कि देश की चाय की चुस्की विश्व के विभिन्न देश ले रहे हैं। हाल ही, में चाय के निर्यात के नवीन आंकड़ें देखने को मिल रहे हैं।

चाय का निर्यात कितने करोड़ किलो हो गया है

भारत से चाय के निर्यात के आंकड़ें समक्ष आ चुके हैं। बीते वर्ष जनवरी से अक्टूबर के मध्य चाय का निर्यात 18.53 करोड़ किलोग्राम तक रहा है। जिसमें 18.1 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन, पूर्व में यह 16 करोड़ किलोग्राम रहा था।

राष्ट्रकुल देशों में सर्वाधिक चाय निर्यात की गई है

चाय बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रकुल देश (सीआईएस ब्लॉक) वर्ष 2022 के पूर्व दस माह में 4 करोड़ 36.5 लाख किलोग्राम चाय आयात कर सर्वोच्च आयातक देशों का समूह रहा। जो कि इससे पहले यह 3 करोड़ 69.5 लाख किलोग्राम पर रहा था। साथ ही, रूस राष्ट्रकुल देशों में 3 करोड़ 28 लाख किलोग्राम की चाय आयात करने सहित सीआईएस ब्लॉक में सर्वोच्च आयातक देश रहा था।

यूएई (UAE) द्वारा 3 करोड़ से ज्यादा का चाय आयात किया है

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने साल 2022 में इसी दौरान में 3 करोड़ 29.5 लाख किलोग्राम सहित दूसरे सर्वोच्च आयातक के तौर पर सामने आया है। बीते वर्ष में इसी समय में यह 1 करोड़ 24.5 लाख किलोग्राम रहा था।

ईरान द्वारा चाय का आयात कम करना चिंता का विषय

ईरान भारतीय चाय का बड़ा खरीदार रहा है। परंतु, वर्तमान में ईरान के चाय आयात के आंकड़ों ने चिंता को काफी बढ़ा दिया है। ईरान द्वारा जनवरी माह से अक्टूबर 2022 तक 1 करोड़ 95.2 लाख किलोग्राम चाय का आयात किया गया है। साल 2021 में इसी दौरान में दो करोड़ 14.5 लाख किलोग्राम से बहुत कम है।

कपास की फसल पैदा करने वाले किसानों का बढ़ा संकट

हाल ही में न्यूज़ में देखा गया की तेलंगाना में कपास की कीमतों में भरी गिरावट दर्ज की गई है, कपास का दाम केवल 6500 रुपये क्विंटल हो या है जिसकी वजह से किसानों की हालत चिंताजनक है। किसानों से हुई बातचीत में पता चला कि वह दाम कम से कम 15000 रुपये क्विंटल चाहते हैं।

इस साल कपास की फसल की बात की जाए तो देश में इस साल किसानों को फसलों का काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ फसल की खेती जैसे पपीता, सेब और संतरे आदि की फसल को भी पहले से ज्यादा नुक्सान पहुंचा है। कभी बाढ़ तो कभी बारिश के कारण किसानों को ये समस्या झेलनी पड़ती है। हाल ही में कपास की कीमत कम होने से किसान परेशान हैं। सही रेट न मिलने से किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है।

तेलंगाना में 6000 रुपये क्विंटल तक हो गया है कपास का मूल्य

इस बार कपास की कीमत का संकट सबसे ज्यादा तेलंगाना के किसानों को परेशान कर रहा है। मीडिया के हवाले पता चला है, कि इस साल का दाम बेहद कम रखा गया है। पहले जिस फसल के लिए 15000 रुपये क्विंटल तक मिलते थे। वो अब महज 6000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। इतने कम दाम होने के कारण किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है।

बारिश के चलते उत्पादन में आई गिरावट

एक्सपर्ट के अनुसार इस बार भारी बारिश के चलते फसल में आई पत्तियों के कारण डोड़े की बढ़त को नुकसान हुआ है। प्रोडक्शन में भारी गिरावट आ गई है। PRODUCTION में करीब 50 प्रतिशत गिरावट आने की संभावना है। वहीं, विशेषज्ञों का कहना है, कि बाजार में कपास की कीमत 6 हजार से लेकर 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसे 15 हजार रुपये प्रति क्विंटल कर देना चाहिए।

कीमत सही न मिलने पर किसान कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन

कपास के सही दाम न मिलने से किसान परेशान हैं। किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है, कि यदि राज्य सरकार 15000 रुपये प्रति क्विंटल कपास का रेट नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन करेंगे।

पंजाब में भी कपास उत्पादकों का है यही हाल

पंजाब में कपास उत्पादन में 45% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 3 सालों से पंजाब में कपास की अच्छी पैदावार हो रही थी। इतनी अच्छी पैदावार से सभी खुश थे, लेकिन हाल ही में यहां कपास में गुलाबी वार्म और कई तरह के कीट होने के कारण किसानों की पैदावार में घटोतरी हुई है।

केंद्र सरकार ने गेंहू के भावों को नियंत्रण करने के लिए जारी की यह योजना

आटे के भावों में बढ़ोत्तरी होने की वजह से केंद्र सरकार बेहद चिंतित है। हाल ही में जारी की गई ओएमएसएस नीति केंद्र सरकार द्वारा आटे की कीमतों के नियंत्रण हेतु लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार लाखों टन गेहूं बाजार में लेकर आएगी, भारत में बढ़ते अनाज के भाव को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार बेहतर निर्णय ले रही है। बीते कुछ महीनों में देश के अंदर गेहूं के मूल्यों में काफी वृद्धि देखने को मिली है। जिसकी वजह से आटे का भाव भी स्वाभाविक रूप से बढ़ा है। बतादें, कि आटे के भाव में वृद्धि के कारण रोटी महंगी हो गयी है, जिससे आम लोगों के घर का बजट बिगड़ना शुरू हो गया है। हालाँकि, केंद्र सरकार इनके बजट को संतुलित करने के लिए पहल कर रही है। केंद्र सरकार का प्रयास है, कि आटे की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके। इस विषय में उच्च स्तर पर कार्य आरंभ हो चुका है।

आटे के भाव कैसे कम करेगी सरकार

मीडिया की खबरों के मुताबिक, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा गेहूं का भाव को लेकर साल 2023 हेतु एक खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) नीति जारी की है। आपको बतादें, कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार थोक विक्रेताओं को एफसीआई द्वारा 15 से 20 लाख टन अनाज जारी किया जायेगा। केंद्र सरकार गेहूं का अच्छा खासा भंडारण रखती है। इसी वजह से अनाज की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, साथ ही इस वर्ष गेहूं की बुवाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। देश में गेहूं की फसल का क्षेत्रफल तीव्रता से बढ़ रहा है।

आटे की कीमतों में वृद्धि का कारण क्या है

यदि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तब हम पायेंगे कि बीते वर्ष इसी गेहूं का औसत खुदरा भाव 28.53 रुपये प्रति किलोग्राम था। दूसरी तरफ इसी समय में 27 दिसंबर 2022 को गेहूं का खुदरा भाव 32.25 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। गेहूं के भाव में वृद्धि तो आटे के भाव को भी इसने काफी प्रभावित किया है। बतादें कि आटे का भाव एक वर्ष पूर्व 31.74 रुपये प्रति किलोग्राम था। लेकिन इस वर्ष इसमें बढ़ोत्तरी होकर 37.25 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत हो गई है। बतादें, कि केंद्र सरकार की ओएमएसएस नीति अत्यंत आवश्यक तो है, ही साथ ही बेहद महत्वपूर्ण भी है। भारत में अनाज संकट की परिस्थिति दिखने एवं सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (FCI) को स्वीकृति प्रदान करती है, कि थोक उपभोक्ताओं एवं निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर गेहूं एवं चावल आदि खाद्यान उत्पाद विक्रय कर दिए जाएंगे। इसकी सहायता से बाजार में उत्पन्न हो रहे, खाद्यान संकट को खत्म किया जाता है।

आखिर क्यों आयी गेंहू के उत्पादन में कमी

केंद्र सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले वर्ष गेहूं की पैदावार में घटोत्तरी सामने आयी थी। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन-रूस युद्ध एवं इसके अतिरिक्त लू का प्रभाव भी गेहूं के उत्पादन पर देखने को मिला है। लू की वजह से गेहूं की फसल को काफी हानि का सामना करना पड़ा है। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो 15 दिसंबर तक केंद्र के पास लगभग 180 लाख टन गेहूं एवं 111 लाख टन चावल का भंडारण था। बतादें कि आपूर्ति में कमी आने की वजह से फसल साल 2021-22 (जुलाई-जून) में गेहूं की पैदावार में घटोत्तरी होकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन तक बचना है। एक वर्ष पूर्व यह वर्ष 10 करोड़ 95.9 लाख टन था। आगामी गेहूं खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी।

औषधीय खेती

इस पौधे के प्रयोग से गंजापन होता है दूर साथ ही चेहरे पर आयेगा नूर

प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ प्रीतिका मजूमदार के अनुरूप ग्वारपाठे मतलब एलोवेरा (ALOE VERA) अत्यंत फायदेमंद पौधा होता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद भी होता है। प्रतिदिन इसका निरंतर उपयोग कर बहुत सारे रोगों व बिमारियों से निजात पा सकते हैं।
घृत कुमारी या ग्वारपाठा मतलब एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जिसका उपयोग बहुत सारी बिमारियों को दूर करने के साथ-साथ सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बाजार में एलोवेरा से निर्मित उत्पाद अपनी विशेष पहचान और स्थान रखते हैं। आज हम इस लेख में जानेंगे, कि कैसे और कौन-सी चीजों में यह अत्यंत लाभकारी होता है।

ग्वारपाठा मतलब एलोवेरा से क्या-क्या लाभ होते हैं

जली त्वचा में लाभकारी

ग्वारपाठे के पत्ते को काटकर इसके अंदर के गूदे को बाहर लेकर के यदि आप त्वचा पर दिन में करीब 23 बार इसका लेप करते हैं, तो आपकी जलन खत्म होकर शीतलता में परिवर्तित हो जाती है।

स्किन टैनिंग के लिए लाभकारी

ग्वारपाठा स्किन टैनिंग को दूर भगाने में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके छिलके को उतारने के उपरांत इसको अच्छी तरह पीसकर जले हुए शारीरिक हिस्से पर लगाने से जख्म ठीक हो जाता है और जलन भी पूरी तरह खत्म हो जाती है।

त्वचा में सौंदर्य और निखार लाए

ग्वारपाठा व एलोवेरा रंग को निखारने में काफी सहायक साबित होता है। अगर आप इसको गुलाब जल में मिश्रित कर के अपनी जांघों पर लगाते हैं, तो इससे आपको पहले से बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ग्वारपाठा यानी एलोवेरा का उपयोग विभिन्न प्रकार के सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। क्योंकि यह त्वचा को नमी उपलब्ध कराके उसको काफी निखार देता है।

सिर सर्द करे जड़ से खत्म

सिर दर्द होने की स्थिति में ग्वारपाठे के गूदे में गेहूं के आटे में मिश्रण कर उसके उपयोग से 2 रोटी बनाएं। रोटी बनने के बाद उसको अच्छी तरह दबाकर के देशी घी में डालें। उस रोटी का सेवन सूर्योदय से पूर्व करलें। इसका नियमित रूप से 57 दिन तक निरंतर सेवन करेंगे तो आपका कैसा भी सिर दर्द हो बिल्कुल सही हो जाएगा।

गंजे के भी सिर पर बाल उगादे

एलोवेरा गंजापन दूर करने में भी काफी सहायक साबित होता है। आपको लाल रंग के ग्वारपाठे जिसके अंतर्गत नारंगी एवं कुछ लाल रंग के फूल होते हैं। उसके गूदे को स्प्रिट में गलाने के उपरांत सिर पर लेप लगाने से गंजे के सिर पर भी बाल आ जाते हैं। इतना ही नहीं यह बालों को काला करने में भी सहायता करता है।

जख्म पर लगाएं ग्वारपाठा

एलोवेरा कुत्ते द्वारा काटने से हुए जख्म को भरने में काफी अच्छा होता है। ग्वारपाठे को एक तरफ से छीलकर इसके गूदे वाले भाग में पिसे हुए सेंधानमक का छिड़काव करें। उसके बाद इसको कुत्ते द्वारा काटी गयी जगह पर लगाऐं। इसका अच्छा फायदा आपको निरंतर इसके चार बार प्रयोग करने के उपरांत ही मिलेगा।

ग्वारपाठा से पिंपल होंगे दूर

आप एलोवेरा के उपयोग से भी पिंपल की समस्या से राहत पा सकते हैं। ऐसे में आप एलोवेरा को प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुछ समय बाद अपनी त्वचा को धो लें।

इस राज्य के किसान अब करेंगे औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती

देश की अन्य राज्य सरकारों की तरह ही जम्मू-कश्मीर की सरकार भी अपने किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत सरकार समय-समय पर राज्य के किसानों को सहायता उपलब्ध करवाती रहती है। इसी के साथ सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी करती है ताकि किसान भाई अपने पैरों पर खड़े रह पाएं।

अब सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों के हितों को देखते हुए एक मेगा प्लान तैयार किया है जिसमें किसानों को अब औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का कहना है, कि जम्मू-कश्मीर के किसान सेब, केसर और बासमती चावल के अलावा औषधीय और सुगंधित पौधों की भी खेती करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही प्रदेश की जीडीपी में भी बढ़ोत्तरी होगी।

इस प्लान के तहत जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कहा है, कि प्रदेश में 625 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की जाएगी। इसके साथ ही सरकार का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के साथ ही प्रदेश के किसान दूसरी अन्य फसलों की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे। जम्मू-कश्मीर राज्य के अधिकारियों का कहना है, कि औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से प्रदेश के किसान 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी सालाना प्राप्त कर सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल बहुत कम खेती की जा रही है। जबकी यहां पर खेती की अपार संभावनाएं हैं। अटल डुल्लू ने कहा कि हिमालय के पास औषधीय और सुगंधित गुण वाले लगभग 1,123 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर किसान इस खेती पर मेहनत करें तो हर साल प्रदेश को करोड़ों रुपये का लाभ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक हर्बल व्यापार लगभग 120 अरब डॉलर का है और भविष्य में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। आंकड़ों के अनुसार यह व्यापार साल 2050 तक 7,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर राज्य के पास इस व्यापार में अपनी जगह बनाने का अच्छा मौका है। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में औषधीय और सुगंधित पौधों का बहुत कम उत्पादन किया जा रहा है।

औषधीय और सुगंधित गुण वाली खेती के मद्देनजर अटल डुल्लू ने बुधवार को तालाब तिल्लो में एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का शुभारंभ किया है। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5200 मीट्रिक टन है। इसके निर्माण के लिए नाबार्ड ने ऋण उपलब्ध करवाया है, जिसे जे एंड के एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड विकसित कर रही है। यह कंपनी जम्मू-कश्मीर सरकार की एक प्रीमियम सरकारी कंपनी है।

अपर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा है, कि इस कोल्ड स्टोरेज का सबसे ज्यादा लाभ राजौरी, पुंछ, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा और अन्य क्षेत्रों के किसानों को होने वाला है। यहां पर ये किसान अपने ताजे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद, फूल, मांस, मछली और अन्य उत्पादों का भंडारण बेहद आसानी से कर सकेंगे। अब किसानों को बिना भाव के सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिससे अब किसानों को पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा और किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

केरल के मुर्गी पालकों की बढ़ी समस्याएं, कहर बरपा रहा है बर्ड फ्लू (BIRD FLU)

हर बार थोड़े-थोड़े समय में हमें बर्ड फ्लू की खबर सुनने को मिल जाती है। बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, जो पक्षियों को प्रभावित करती है। जबकि मनुष्य आमतौर पर इस वायरस के संपर्क में नहीं आते हैं। बर्ड फ्लू (BIRD FLU) या एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली स्थिति है। जो आमतौर पर जंगली जलीय पक्षियों में देखी जाती है। यह घरेलू पोल्ट्री, अन्य पक्षियों और जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है।

हाल ही में केरल राज्य में बर्ड फ्लू (BIRD FLU) की खबर आ रही है और रिपोर्ट की मानें तो यहां पर लगभग 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू ज्यादातर बतख और मुर्गियों को प्रभावित करता है। जिससे पोल्ट्री फार्म (POULTRY FARM) में एक साथ सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों और बत्तखों सहित अन्य पक्षियों की मौत हो जाती है। जब भी बर्ड फ्लू फैलता है, यह मुर्गी पालन का व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बेहद परेशानी का कारण बन जाता है। साथ ही, उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ आलम आजकल केरल के मुर्गी पालकों का है। यहां भारी मात्रा में मुर्गियों की बर्ड फ्लू से मौत हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, केरल के तिरुवनंतपुरम जिला स्थित पेरुंगुझी में एक फार्म में एवियन फ्लू से 200 बत्तखों की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की है। वहीं, बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए पशुपालन विभाग ने तिरुवनंतपुरम में कई स्थानों पर पक्षियों को मारना शुरू किया। वार्ड सदस्यों की मदद से पेरुंगुझी जंक्शन वार्ड के एक किलोमीटर के दायरे में 3000 तक पक्षियों को मार गया है।

डॉक्टर को तुरंत सूचना दें

अगर रिपोर्ट की मानें तो जिन पक्षियों को बर्ड फ्लू हुआ है उनके अंडे, मांस, चारा और गोबर का भी निस्तारण किया जा रहा है। खास बात यह है, कि सरकार ने विभाग के निगरानी क्षेत्र की घोषणा में किझुविलम, कडक्कवूर, कीझाटिंगल, चिरायिंकीझू, मंगलापुरम, अंदूरकोणम और पोथेनकोड पंचायत को शामिल किया है। इसके अलावा इस माहौल में स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है, कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को दें।

बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों को संभालते हुए कैसे रखें अपना ख्याल

मुर्गियां, बत्तख, गीज़, बटेर, टर्की और अन्य पालतू पक्षियों को राज्य में बर्ड फ़्लू होने की सूचना मिली है। हालांकि, राज्य को अभी तक लोगों में एवियन फ्लू के संक्रमण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने उन सभी व्यक्तियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, जो मुर्गी पालन में लगे हैं या फिर किसी भी तरह से बर्ड फ्लू होने वाले पक्षियों के संपर्क में आए हैं। डॉक्टर कुछ शुरुआती इलाज करने के बाद इसके निवारण के लिए दवाइयां दे देते हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। सभी लोगों को आदेश दिए गए हैं, कि जब भी वह बर्ड फ्लू से संक्रमित होने वाले किसी भी पक्षी को संभाल रहे हैं तो दस्ताने और मास्क पहनना ना भूलें।

साथ ही, बार बार साबुन से हाथ धोने की सलाह भी दी गई है। शरीर में गंभीर दर्द, बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, सर्दी और कफ में खून आने जैसी शिकायत आने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही गई है। हालांकि बर्ड फ्लू मनुष्य को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। लेकिन फिर भी कुछ मामले देखे गए हैं, जिसमें यह बीमारी लोगों को हो सकती है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकती है।

मधुमक्खी पालकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी

शहद के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है। प्राकृतिक मिठास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह गुणकारी चीज घर घर में पाई जाती है। आजकल लोग भारी मात्रा में मधुमक्खी पालन करते हैं और इस व्यवसाय से काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

आपके लिए शायद यह नई बात होगी, लेकिन मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मधुमक्खी पालन में अड़चन बन जाते हैं। साथी ही, मधुमक्खियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। हाल ही में मधुमक्खी पालन संघ के बोर्ड के मेंबर ट्रेवर टॉज़र ने सभी मधुमक्खी पालकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर दी है। उनके अनुसार, नया टीका 'मधुमक्खी पालकों के लिए एक रोमांचक कदम' हो सकता है। उनके द्वारा की गई बातचीत से पता चलता है, कि इस टीके का इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत महंगे उपचार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस व्यवसाय के बाकी क्षेत्रों पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं।

देश दुनिया के सभी मधुमक्खी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए यह खबर बेहद खुशखबरी लेकर आई है। क्योंकि अब उनकी मधुमक्खियां पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहेगी, जिससे शहद का उत्पादन भी अपने आप ही बढ़ेगा।

शहद के गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है। प्राकृतिक मिठास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यह गुणकारी चीज घर घर में पाई जाती है। आजकल लोग भारी मात्रा में मधुमक्खी पालन करते हैं और इस व्यवसाय से काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

आपके लिए शायद यह नई बात होगी, लेकिन मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो मधुमक्खी पालन में अड़चन बन जाते हैं। साथी ही, मधुमक्खियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। हाल ही में मधुमक्खी पालन संघ के बोर्ड के मेंबर ट्रेवर टॉज़र ने सभी मधुमक्खी पालकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर दी है। उनके अनुसार, नया टीका 'मधुमक्खी पालकों के लिए एक रोमांचक कदम' हो सकता है। उनके द्वारा की गई बातचीत से पता चलता है, कि इस टीके का इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत महंगे उपचार करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस व्यवसाय के बाकी क्षेत्रों पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं।

देश दुनिया के सभी मधुमक्खी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए यह खबर बेहद खुशखबरी लेकर आई है। क्योंकि अब उनकी मधुमक्खियां पहले के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहेगी, जिससे शहद का उत्पादन भी अपने आप ही बढ़ेगा।

मधुमक्खियों के लिए बने इस टीके के उपयोग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। इस टीके को मधुमक्खी कालोनियों को अमेरिकी फाउलब्रूड रोग से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दरअसल, फाउलब्रूड एक ऐसा रोग है, जो जीवाणु संक्रमण का एक रूप है और यह सीधा मधुमक्खी के लारवा पर हमला करता है और मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी को कमजोर कर देता है।

डालन एनिमल हेल्थ के सीईओ एनेट क्लेसर ने हाल ही में हुई बातचीत में बताया कि, मधुमक्खियां एक ऐसा जीव है जो ईको सिस्टम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इस टीके को मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए भी एक बहुत ही कामयाब पहल मानी जा रही है।

इन सबके साथ ही बायोटेक फॉर्म के अनुसार अमेरिकी कृषि विभाग ने इसी सप्ताह ही इस वैक्सीन के लिए लाइसेंस को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र एफएओ के अनुसार, मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे परागणकों का वैश्विक फसल उत्पादन में लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

रिपोर्ट की मानें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी साल 2006 से मधुमक्खियों की कॉलोनियों में काफी ज्यादा कमी आई है। इसके लिए बहुत से कारक जिम्मेदार माने गए हैं। यह सभी कारक अंततः जाकर मधुमक्खी के स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। बहुत से परजीवी और कीट मधुमक्खियों की सेहत के लिए काफी हानिकारक होते हैं। कई बार मधुमक्खियों को इनके कारण इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इस वैक्सीन का वितरण सभी तरह के मधुमक्खी योजना में एक योजना के अनुसार किया जाएगा

नंदी रथ के जरिए किसान कर रहे हैं हर महीने कमाई, जाने क्या है तरीका

आजकल भारत में गौवंश को बचाने की बहुत बड़ी पहल चल रही है। देशी गौवंश के संरक्षण के बारे में बढ़-चढ़कर बात की जा रही है और साथ ही गौवंश ऊपर आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज किसानों के लिए निराश्रित गौवंश बड़ी समस्या बनती जा रही है। लेकिन देसी गौवंश में सबसे बड़ी बाधा दूध ना देने वाले पशु यानी बछड़े और बैल ही बनते हैं, जिनकी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। यही वजह है, कि आप को सड़कों पर हर जगह यह बैल घूमते हुए नजर आते रहते हैं और इनकी हालत बेहद खराब होती है।

लेकिन आज हम आपको यह बताना चाहते हैं, कि इन निराश्रित पशुओं की अहमियत को समझें और इन्हें बोझ की तरह नहीं बल्कि कमाई का साधन बना कर अच्छी तरह से इनका ध्यान रखें। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि यह नर पशु आपको स्वयं अपना सारा भी कमा कर देंगे और इसके अलावा आपके घर में आमदनी के साधन भी बन सकते हैं।

क्या है नंदी रथ?

आपको यह बात हैरान कर देगी। लेकिन आजकल बैलों के माध्यम से देश के कई इलाकों में बिजली बनाई जा रही है। यह बिजली उन्हें निराश्रित बैलों के माध्यम से बनाई जा रही है, जिन्हें आप सड़कों पर आवारा घूमते हुए देख सकते हैं। आवारा पशु एक तरह से गौशाला के ऊपर बोझ ही होते हैं, जिनकी देखभाल और खान-पान आदि पर सरकार का खर्च बढ़ जाता है। यदि सरकार इन्हीं गौवंशों को बिजली बनाने के काम पर लगा दे, तो इन गौवंशों की वैल्यू बढ़ेगी और कमाई भी होगी।

लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर गोसाईगंज के सिद्धुपुरवा गांव में भी एक ऐसे ही मॉडल पर काम चल रहा है। यहां पर एक गौशाला बैलों को ट्रेडमिल पर चलाती है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। अगरसूत्रों की मानें तो गौशाला ने यह कांसेप्ट नंदी रथ से लिया है। इसलिए इसका नाम नंदी रथ योजना रखा गया है।
इस नंदी रथकर पर बैलों को चढ़ा दिया जाता है, साथ में चारे का इंतजाम भी होता है। ये बैल चारा खाते हैं और ट्रेडमील पर चलते हैं। बदले में ट्रेडमील को गियर बॉक्स से जोड़ा गया है, जो 1500 आरपीएम पावर को कन्वर्ट कर रहा है।

बढ़िया हो रहा है बिजली उत्पादन

रिपोर्ट की मानें तो गौशाला के मालिक पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने खुद यह बात बताई है, कि 1500 आरपीएम पर ही बिजली निर्माण होता है। अभी तक पूरी दुनिया में 500 से 700 आरपीएम ही लिया गया है। लेकिन इस गैशाला में लगे गियरबॉक्स (GEARBOX) ने अधिक बिजली मात्रा में बिजली लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। इस मॉडल को बाकायदा पेटेंट करवाया गया है।
इस मॉडल से बनाई गई बिजली से किसान ना सिर्फ अपनी कृषि से जुड़ी हुई जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बल्कि उनके घर के तमाम उपकरण भी इसी बिजली से चलाए जा रहे हैं। मीडिया से हुई बातचीत में शैलेंद्र सिंह ने बताया कि सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली के लिए भी हमें ₹3 प्रति यूनिट देना पड़ता है। जबकि नंदी रथ योजना के तहत बन रही बिजली मात्र 1.5 रुपये में ही मिल सकती है।

किसानों की कितनी कमाई हो जाएगी

आंकड़ों की मानें तो नंदी रथ के जरिए बैलों से बनाई गई बिजली के आधार पर किसान हर महीने 4000 से ₹5000 की आमदनी सीधे तौर पर कमा सकते हैं। यह कमाई तो सिर्फ बिजली से होगी। इसके अलावा, बैलों से मिलने वाले गोबर से आप वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद आदि बनाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन दिनों पर्यावरण सरंक्षण में जैविक खेती और ग्रीन एनर्जी (GREEN ENERGY) का चलन बढ़ता जा रहा है।
माना जा रहा है, कि यह कांसेप्ट भी आगे चलकर सौर ऊर्जा की तरह ग्रीन एनर्जी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण बन सकता है। यहां पर एक और अच्छी बात यह है. कि बहनों से बन रही बिजली के उत्पादन में पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। जबकि सोलर उत्पादन में भी लगभग 25 साल बाद डिस्पोजल की समस्या को गंभीर होने का खतरा माना गया है।

मोटा अनाज हो सकता है आपके पशुओं के लिए घातक

हम सभी जानते हैं, कि यह साल विश्व में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (आईवायओएम/IYOM) के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी तरह के मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है, कि मोटे अनाज का सेवन करना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह न सिर्फ आपको स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखता है, बल्कि यह हमारी प्रतिरक्षा (IMMUNITY) बढ़ाने के लिए भी बेहद जरूरी है।

अगर आप नियमित रूप से मोटे अनाज का सेवन करते हैं, तो यह आपके प्रतिरक्षा प्रणाली (IMMUNE SYSTEM) को स्ट्रांग करता है। आपको बहुत तरह के रोगों से दूर रखता है। मोटा अनाज इंसानों के अलावा पशुओं के लिए भी काफी लाभकारी माना गया है। लेकिन हमें यह भी जानने की जरूरत है, कि मोटा अनाज कभी-कभी पशुओं के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे।

पशुओं को किस तरह से खिलाया जाए बाजरा

अगर आप अपने पशुओं के आहार में बाजरे को मिलाना चाहते हैं, तो आप इसका दलिया बनाकर उसे अच्छी तरह से पका कर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपने पशुओं को खिला सकते हैं। साथ ही, आप पशुओं के चारे में बाजरे का आटा मिलाकर भी उन्हें खिला सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी लेकिन पशुओं को भी थोड़े बहुत नमक की जरूरत होती है। इसलिए अगर जरूरत पड़े तो आप इस आटे में चुटकी भर नमक भी मिलाकर पशुओं को दे सकते हैं। रोजाना बात की जाए तो आप 1 से 2 किलो बाजरा अपने पशुओं को खिला सकते हैं। बाजरे का आटा खिलाने का सबसे बड़ा फायदा यह है, कि यह आपके पशुओं को वजन बढ़ाने में मदद करता है।

पशुओं को बाजरा खिलाने के क्या है फायदे

पशुओं को बहुत पहले से बाजरा या फिर बाजरे का आटा खिलाया जाता रहा है। अगर आप के पशु को लिवर से जुड़ी हुई किसी तरह की समस्या है, तो आप उसे बेझिझक बाजरा खिला सकते हैं यह उसके लिए काफी लाभदायक होगा। बाजरा पशुओं के पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बहुत से मामलों में ऐसा होता है, कि बच्चा पैदा करने के बाद पशु बीमार रहने लगता है। ऐसे मामले में आप उसे बाजरा खिला सकते हैं। यह न सिर्फ उसे बीमारियों से दूर रखेगा बल्कि यह पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा सहायक है। आप छोटे पशुओं जैसे कि बछड़े आदि को भी बाजरे के आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर खिला सकते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है।

बाजरा खिलाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं

हमने मोटे अनाज जैसे कि बाजरे आदि का पशुओं के आहार में फायदा तो देख लिया है। लेकिन कई बार इसके बहुत से नुकसान भी देखे जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक अपने पशुओं को बाजरे का आटा या फिर बाजरे का दलिया खिलाते रहते हैं। तो उन में आयरन की कमी हो सकती है। इससे पशु की बॉडी पर गांठें उभरने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप जरूरत से ज्यादा बाजरा पशुओं को खिला रहे हैं, तो उनमें अफारे की समस्या देखने को मिल सकती है। पशु चिकित्सक और एक्सपर्ट का कहना है, कि कभी भी किसी जानवर को बिना डॉक्टर की सलाह के बाजरा नहीं खिलाया जाना चाहिए। अगर आप इसे खिला भी रहे हैं, तो इसकी मात्रा हमेशा सीमित रखें।

अब खास तकनीक से पैदा करवाई जाएंगी केवल मादा भैंसें और बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन

अब भारत के किसान खेती बाड़ी के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं। इस तरह से अपनी आमदनी को दोगुना करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों द्वारा की जा रही यह पहल ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रही है बल्कि भारत में बढ़ रहे डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए भी यह बेहतरीन विकल्प है। कुछ समय पहले तक दुधारू पशुओं की संख्या एक चुनौती बनी हुई थी। लेकिन सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए काफी प्रयास किया है और अब देश में मादा दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ तकनीक चलाई जा रही हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक के तहत मादा भैंसों की पैदाइश बढ़ाई जाएगी और नर भैंसों को पैदा होने से रोका जा सकता है।

देशभर में पहले से ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है और उसी के तहत नस्ल सुधार कार्यक्रम के भीतर इस तकनीक को प्रमोट किया जाएगा। इस तकनीक में सबसे ज्यादा ध्यान मादा भैंसों की संख्या बढ़ाने पर ही रहेगा।

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ऑफ भोपाल मदर बुल फॉर्म में भी अब गौवंशों के साथ भैंसवंशों के नस्ल सुधार का काम चल रहा है। इससे राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और श्वेत क्रांति में योगादान देने में खास मदद मिलेगी।

पैदा होंगी केवल मादा भैंस

सेक्स सीमन सॉर्टेड तकनीक पहले ब्राजील में इस्तेमाल की जाती रही है और इसके तहत वहां पर मादा भैंसों का जन्म करवाया जाता रहा है। इसी तकनीक की तर्ज पर अब भारत में भी यह अपनाया जाएगा। अब ब्राजील की तरह मादा पशुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश का कुटकुट विकास निगम अब भैंसों में सेक्स सॉर्टेड सीमन की तकनीक का परीक्षण करेगा।

इस तकनीक के तहत मादा पशुओं को आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण करवाया जाएगा। इस तरह से गर्भधारण होगा कि केवल मादा भैंस ही जन्म लेगी और नर पशु के जन्म को रोक दिया जाएगा।

अगर पशुपालन विभाग में रहने वाले एक्सपर्ट लोगों की बात मानी जाए तो इस तकनीक के जरिए पैदा होने वाली भैंस में दूध की क्षमता बाकी के मुकाबले ज्यादा होगी। इस तकनीक से पैदा हुई भैंस रोजाना 20 लीटर तक दूध का उत्पादन करने में मदद करेगी।

इससे किसान और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसी तकनीक की तर्ज पर ब्राजील ने भारत के देसी पशुधन के जरिए 20 से 54 लीटर तक दूध उत्पादन लेने का रिकॉर्ड कायम किया है।

इन भैसों की नस्लों का होगा सुधार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश कुटकुट विकास निगम के सहयोग से मदर बुल फॉर्म स्थित लैब मुर्रा नस्ल के बफेलो बुल से सेक्स सॉर्टेड सीमन से 50,000 स्ट्रा तैयार किए जा रहे हैं। भैंसों के इस नस्ल सुधार कार्यक्रम में मुर्रा, जाफराबादी और भदावरी प्रजाति की भैसों को शामिल किया गया है।

इस प्रोजेक्ट के पहले चरण की बात की जाए तो सबसे पहले ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस में सुधार होगा। माना जाता है, कि मुर्रा नस्ल की भैंस अभी 8 से 10 लीटर तक दूध देती है। अगर इस तकनीक के जरिए नस्ल बढ़ाई जाती है, तो दूध उत्पादन बढ़कर 18 से 20 लीटर तक हो जाएगा।

इस तकनीक के तहत मादा पशुओं को आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण करवाया जाएगा। इस तरह से गर्भधारण होगा कि केवल मादा भैंस ही जन्म लेगी और नर पशु के जन्म को रोक दिया जाएगा।
अगर पशुपालन विभाग में रहने वाले एक्सपर्ट लोगों की बात मानी जाए तो इस तकनीक के जरिए पैदा होने वाली भैंस में दूध की क्षमता बाकी के मुकाबले ज्यादा होगी। इस तकनीक से पैदा हुई भैंस रोजाना 20 लीटर तक दूध का उत्पादन करने में मदद करेगी।
इससे किसान और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसी तकनीक की तर्ज पर ब्राजील ने भारत के देसी पशुधन के जरिए 20 से 54 लीटर तक दूध उत्पादन लेने का रिकॉर्ड कायम किया है।

इन भैसों की नस्लों का होगा सुधार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश कुटकुट विकास निगम के सहयोग से मदर बुल फॉर्म स्थित लैब मुर्रा नस्ल के बफेलो बुल से सेक्स सॉर्टेड सीमन से 50,000 स्ट्रा तैयार किए जा रहे हैं। भैंसों के इस नस्ल सुधार कार्यक्रम में मुर्रा, जाफराबादी और भदावरी प्रजाति की भैसों को शामिल किया गया है।
इस प्रोजेक्ट के पहले चरण की बात की जाए तो सबसे पहले ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली मुर्रा नस्ल की भैंस में सुधार होगा। माना जाता है, कि मुर्रा नस्ल की भैंस अभी 8 से 10 लीटर तक दूध देती है। अगर इस तकनीक के जरिए नस्ल बढ़ाई जाती है, तो दूध उत्पादन बढ़कर 18 से 20 लीटर तक हो जाएगा।
पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि मुर्रा प्रजाति हरियाणा से ताल्लुक रखती है। जिसे दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार करने में 35 साल का समय लगा। अब इससे दूसरी नस्लों का सुधार किया जा रहा है।

सामान्य लेख

MERIKHETI.COM ने राजस्थान में फरवरी की मासिक किसान पंचायत का आयोजन किया

MERIKHETI.COM के द्वारा मासिक किसान पंचायत 12 फरवरी 2023 दिन रविवार को गाँव सीथल, जिला अलवर (राजस्थान) की जय हिन्द नर्सरी में आयोजित की गयी। मासिक किसान पंचायत के दौरान किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों एवं तकनीकों के बारे में बताया गया था। MERIKHETI.COM द्वारा प्रत्येक माह किसान मासिक पंचायत का आयोजन किया जाता है। जिससे कि किसानों को वर्तमान में कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन के बारे में बताया जा सके साथ ही उनकी आय में बढ़ोत्तरी करके उनको अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

किसानों के हित में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक मौजूद रहते हैं। किसान बेझिझक अपने सवाल पूछते हैं, जिनका उत्तर कार्यक्रम में उपस्थित कृषि विशेषज्ञ विस्तृत रूप में देते हैं। किसान मासिक पंचायत के दौरान डॉ सी.बी. सिंह प्रिंसिपल साइंटिस्ट (RETD) IARI , डॉ विपिन शर्मा कृषि वैज्ञानिक (KVK) G. B नगर और डॉ हरीश कुमार कृषि वैज्ञानिक PUSA (ICAR) सहित अन्य बहुत से कृषि क्षेत्र से जुड़े दिग्गज वैज्ञानिक उपस्थित रहे।

इस मासिक किसान पंचायत में वैज्ञानिकों ने गाँव सीथल (भिवाड़ी) के किसानों को खेती की ऊपज बढ़ाने के लिए कई नुस्खों और तकनीकों के बारे में बताया। सीथल गाँव शुष्क इलाकों में आता है यहां खेती वर्षा पर ही आधारित है यहां के किसानों को बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा की आप जैविक खेती को अपना कर भी अच्छी पैदावर ले सकते है। वैज्ञानिकों ने किसनो को संजीवक, जीवामृत बनाने की विधि के बारे में बताया। ये दोनों घोल बनाने की विधि निम्नलिखित है।

संजीवक घोल को बनाने की विधि इस प्रकार है

संजीवक का उपयोग सूक्ष्मजीवों और त्वरित अवशेषों के अपघटन के साथ मिट्टी को समृद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सबसे पहले आपको 500 लीटर के बंद ड्रम में 300 लीटर पानी में 100-200 किलो गाय का गोबर, 100 लीटर गोमूत्र और 500 ग्राम गुड मिलाना है। इसके बाद इस ड्रम को बंद करके 10 दिनों के लिए गलने के लिए रख दे। 10 दिनों बाद ये संजीवक घोल बनकर तैयार हो जाता है। इसका प्रयोग 20 गुना पानी में घोलकर एक एकड़ में या तो मिट्टी के स्प्रे के रूप में या सिंचाई के पानी के साथ छिड़काव करें।संजीवक घोल का छिड़काव सिंचाई के पानी के माध्यम से उपयोग किया जाता है।

तीन बार इस घोल का छिड़काव करने से फसल की ऊपज में बढ़ोतरी होती है, एक बुवाई से पहले, दूसरा बुवाई के बीस दिन बाद और तीसरा बुवाई के 45 दिन बाद।

जीवामृत बनाने की विधि

एक बैरल/ड्रम में 100 लीटर पानी लें और 10 किलो गाय का गोबर और 10 लीटर गोमूत्र में मिलाएं। इसके बाद दो किलो गुड़ और दो किलो चना या कोई भी दाल का आटा इस घोल में लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह मिला लें। इस घोल को 5 से 7 दिन के लिए गलने के लिए रख दें। घोल को नियमित रूप से दिन में तीन बार हिलाएं।

जीवामृत का छिड़काव करके या सिंचाई के पानी के माध्यम से मिट्टी में मिला कर इसका उपयोग किया जाता है। तीन बार इस घोल को उपयोग करने की जरूरत है एक बुवाई से पहले, दूसरा बुवाई के बीस दिन बाद और तीसरा बुवाई के 45 दिन बाद। इस प्रकार यदि किसान इस घोल को प्रयोग करते है तो फसल की ऊपज में इजाफा होता है।

जीवामृत बनाने की विधि

एक बैरल/ड्रम में 100 लीटर पानी लें और 10 किलो गाय का गोबर और 10 लीटर गोमूत्र में मिलाएं। इसके बाद दो किलो गुड़ और दो किलो चना या कोई भी दाल का आटा इस घोल में लकड़ी की डंडी से अच्छी तरह मिला लें। इस घोल को 5 से 7 दिन के लिए गलने के लिए रख दें। घोल को नियमित रूप से दिन में तीन बार हिलाएं।

जीवामृत का छिड़काव करके या सिंचाई के पानी के माध्यम से मिट्टी में मिला कर इसका उपयोग किया जाता है। तीन बार इस घोल को उपयोग करने की जरूरत है एक बुवाई से पहले, दूसरा बुवाई के बीस दिन बाद और तीसरा बुवाई के 45 दिन बाद। इस प्रकार यदि किसान इस घोल को प्रयोग करते है तो फसल की ऊपज में इजाफा होता है।

वैज्ञानिकों द्वारा विकिसत की गई शिमला मिर्च की नई किस्म से किसानों को होगा दोगुना मुनाफा

आईसीएआर शिमला केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा शिमला मिर्च की 562 नवीन किस्म विकसित कर दी है। वर्तमान में किसान 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हाँसिल कर रहे हैं। लेकिन शिमला मिर्च की इस नई प्रजाति से किसान भाई 50 क्विंटल तक पैदावार उठा सकते हैं।

भारत में किसान खेती को तकनीकी समझदारी से कर के लाखों रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं। किसानों का भी यही प्रयास रहता है, कि कैसे वह बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिकों द्वारा भी निरंतर ऐसे बीज तैयार करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जिनसे किसान खेती कर बुवाई कर मोटा उत्पादन ले सकें।

वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित की गई नवीन प्रजातियों में जल की आवश्यकता न्यूनतम रहती है। साथ ही, खर्च कम होता है, जबकि आय बहुत ज्यादा हो जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला ने पहाड़ी राज्यों हेतु शिमला फसल का नवीन बीज विकसित कर दिया है। इस बीज से पैदावार कर किसान ढाई गुना तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

किसान भाई शिमला मिर्च की नई किस्म से पाएंगे 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन

किसान भाई इस बीज का उपयोग कर अच्छी-खासी पैदावार ले सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताय है, कि हाइब्रिड शिमला मिर्च की 562 बीज तैयार हो चुका है।

इन तीन राज्यों में उत्पादन कर पाएंगे किसान भाई

वैज्ञानिकों ने बताया है, कि नवीन किस्मों को विकसित करने हेतु राज्य विशेष की जलवायु एवं मृदा व सिंचाई की उपलब्धता एवं अन्य कारकों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर का पर्यावरण बीज हेतु अनुकूल पाया गया है। यहां किसान इसका उत्पादन करके बेहतर उत्पादन अर्जित कर रहे हैं।

200 क्विंटल ब्रीडर बीज मुहैय्या कराया गया है

आईसीएआर शिमला मिर्च वैज्ञानिकों द्वारा हाइब्रिड बीज भारत के तीन पहाड़ी राज्यों हेतु तैयार हुआ है। आईसीएआर शिमला सेंटर द्वारा इन तीन राज्यों हेतु 300 क्विंटल ब्रीडर बीज मुहैय्या कराया जाना है। जिसमें से एकमात्र हिमाचल प्रदेश के खाते में 200 क्विंटल ब्रीडर बीज जाना है।

इतने किलो ब्रीडर बीज से 2000 क्विंटल बीज होगा तैयार

आईसीएआर (ICAR) शिमला मिर्च की ब्रीड बीज राज्य सरकारों के लिए भी उपलब्ध किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है, कि 100 किलो ब्रीडर बीज द्वारा 2000 क्विंटल बीज निर्मित कर दिया गया है। इतना ज्यादा बीज होने की वजह से किसानों का बुवाई कार्य बेहद सुगमता से हो रहा है। किसानों को खेती करने के लिए बीज हेतु इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। किसानों के लिए राज्य सरकार सुगमता से बीज मुहैय्या करा रही है।

मिट्टी की सेहत - खाद

मथुरा में बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) बनाने जा रहा है अडानी ग्रुप, साथ ही, गोबर से बनेगी CNG

उत्तर प्रदेश के मथुरा में आने वाले बरसाने की श्रीमाता गौशाला से प्रति दिन 35 से 40 टन गोबर निर्मित होता है। इसलिए अडानी कंपनी द्वारा 200 करोड़ के खर्च से गोबर गैस प्लांट (GOBAR GAS PLANT) स्थापित कर रही है, जिसमें बायोगैस CNG सहित उर्वरक भी निर्मित किया जाएगा।

जब भी गाय पालन एवं गौ सेवा की बात सामने आती है, तब मस्तिष्क में मथुरा-वृंदावन की एक छवि का दर्शन होता है। यहां पौराणिक काल से ही गाय पालन का विशेष महत्व है। पूर्ण विश्व ब्रज क्षेत्र को दूध हब के रूप में जानता है। परंतु, अब इसकी पहचान बायोगैस हब के रूप में की जाती है। हालाँकि, मथुरा में बहुत पहले से रिफाइनरी उपस्थित है। परंतु, फिलहाल निजी कंपनियां भी मथुरा के अंदर बायोगैस सीएनजी एवं खाद निर्मित करने हेतु निवेश किया जा रहा है।

भारत की बड़ी कंपनियों में शम्मिलित अडानी ग्रुप की टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा अब बरसाना स्थित रमेश बाबा की श्रीमाता गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना पर कार्य चल रहा है।

आपको बतादें कि 200 करोड़ के खर्च से स्थापित होने वाला यह बायोगैस प्लांट सीएनजी सहित तरल उर्वरक नहीं निर्मित करेगा। जिसके लिए श्री माता गौशाला से प्राप्त होने वाले गोबर का उपयोग किया जाएगा। इस प्लांट हेतु किसानों एवं पशुपालकों से भी गोबर खरीदने की योजना है।

अडानी ग्रुप निर्मित करेगा सीएनजी (CNG) एवं गोबर

भारत की बड़ी गौशालाओं में शम्मिलित बरसाना की श्री माता गौशाला के अंदर गौ सेवा सहित आमदनी का सृजन भी होगा। खबरों के मुताबिक, तो अड़ानी टोटल गैस लिमिटेड द्वारा रमेश बाबा की श्री माता गौशाला से मिलकर समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत गौशाला की भूमि पर ही बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) स्थापित किया जाना है। इस 13 एकड़ में विस्तृत प्लांट 40 टन गोबर की क्षमता रखता है, जिससे कि 750 से 800 किलो तक सीएनजी की पैदावार उठायी जा सकती है। साथ ही, प्लांट से प्राप्त होने वाला तरल खाद भी किसानों को मुहैय्या कराया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत गौशाला के अंदर निर्मित किया जा रहा है। अडानी ग्रुप का बायोगैस प्लांट 20 वर्ष हेतु गौशाला की भूमि का उपयोग करेगा।

जिसके बदले में गौशाला को किराया एवं गोबर के बदले भुगतान भी प्रदान किया जाना है। केवल इतना ही नहीं, यहां निर्मित होने वाला बायोगैस CNG विक्रय कर जो आय होनी है। जिसका एक भाग गौशाला में गो सेवा पर भी व्यय होगा।

जिसके बदले में गौशाला को किराया एवं गोबर के बदले भुगतान भी प्रदान किया जाना है। केवल इतना ही नहीं, यहां निर्मित होने वाला बायोगैस CNG विक्रय कर जो आय होनी है। जिसका एक भाग गौशाला में गो सेवा पर भी व्यय होगा।

इन प्रसिद्ध डेयरियों ने भी बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) की स्थापना की है
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कभी कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित रहती थी। वह अब गोबर से आय के मॉडल को तीव्रता से अपना रही है। वर्तमान में बहुत से किसान-पशुपालक बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) स्थापित करके तरल खाद सहित व्यक्तिगत जरूरतों को पूर्ण करने हेतु बायोगैस का निर्माण कर रही हैं। इससे बहुत सारे घरों का चूल्हा चलता है। गोबर के मॉडल में तीव्रता से आने वाली वृद्धि से मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसलिए वर्तमान में बहुत सारी कंपनियों द्वारा इस मॉडल पर निवेश किया जा रहा है। अडानी समूह से पूर्व अमूल कंपनी द्वारा भी गुजरात में भी ऐसा ही बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। हरियाणा की वीटा डेरी द्वारा भी नारनौल में इसी तरह के प्लांट पर कार्य किया जा रहा है।

इन प्रसिद्ध डेयरियों ने भी बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) की स्थापना की है

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कभी कृषि एवं पशुपालन पर आश्रित रहती थी। वह अब गोबर से आय के मॉडल को तीव्रता से अपना रही है। वर्तमान में बहुत से किसान-पशुपालक बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) स्थापित करके तरल खाद सहित व्यक्तिगत जरूरतों को पूर्ण करने हेतु बायोगैस का निर्माण कर रही हैं। इससे बहुत सारे घरों का चूल्हा चलता है। गोबर के मॉडल में तीव्रता से आने वाली वृद्धि से मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसलिए वर्तमान में बहुत सारी कंपनियों द्वारा इस मॉडल पर निवेश किया जा रहा है। अडानी समूह से पूर्व अमूल कंपनी द्वारा भी गुजरात में भी ऐसा ही बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। हरियाणा की वीटा डेरी द्वारा भी नारनौल में इसी तरह के प्लांट पर कार्य किया जा रहा है।

देश की कई बड़ी कंपनियां गोबर से करोड़ों की कमाई करने की तैयारी कर रही हैं. इसी गोबर से रसोई गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी गैस बनाई जा रही है. साथ ही,फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बनाए जा रहे हैं.

बायोगैस पूर्व से ही निर्मित की जा रही है

किसान तक की रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा के बरसाना स्थित रमेश बाबा की श्री माता गौशाला में पूर्व से ही एक बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है। जिससे प्रत्येक दिन 25 टन गोबर से बायोगैस निर्मित की जाती है। इस गैस के माध्यम से ही गौशाला रौशन रहती है। बायोगैस प्लांट (BIOGAS PLANT) से निकलने वाली गैस द्वारा 100 केवी का विद्युत जनित्र संचालित होता है। गौशाला के विभिन्न कार्यों हेतु विघुत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

बदली MBA पास की किस्मत, अमरूद की खेती से बना करोड़पति

आज का अधिकांश युवा वर्ग खेती किसानी की तरफ रुख कर रहा है. इससे उन्हें उनके सुनहरे भविष्य को नये पंख लग रहे हैं. नई सोच और नई तकनीक से खेती के मायने बदलने वाले युवाओं में से एक हैं MBA पास राजीव भास्कर. जो अमरूद बेचकर करोड़पति बन गये हैं.

राजीव भास्कर का जन्म नैनीताल में हुआ था. उन्होंने रायपुर की एक बीज कंपनी में भी काम किया. जिसमें उन्हें विशेषज्ञता मिली. जिस वजह से वो आज एक समृद्ध और उद्यमी किसान बन सके. राजीव ने बताया कि, उन्होंने बिक्री और मार्केटिंग के मेंबर के तौर पर VNR सीड्स कंपनी में करीब चार सालों तक काम किया. इस दौरान उन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्र के कई किसानों के साथ मुलाकात की. जिसके बाद उन्हें खेती और किसानी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली. इन्हीं जानकारियों के दम पर राजीव भास्कर ने नौकरी छोड़ कर खेती करने का फैसला किया.

MBA पास कर शुरू की खेती

राजीव भास्कर ने कृषि से BSC पूरा किया. हालांकि जब तक उन्होंने VNR बीजों के साथ काम करना नहीं शुरू किया था, तब तक खेती किसानी की दिशा में उन्होंने आगे बढ़ने के बारे में भी नहीं सोचा था. जिस बीच राजीव ने MBA का कोर्स कर लिया. जो DISTANCE LEARNING था. राजीव भास्कर बताते हैं कि, जैसे जैसे उन्होंने बीजों और पोधौं को बेचने का काम शूरू किया, वैसे वैसे कृषि में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती गयी. जिसके बाद उन्होंने इस ओर काम करने का मन बना लिया. नौकरी के साथ ही राजीव ने अमरूद की थाई किस्म के बारे में जाना और समझा. जिसने बाद उन्होंने इसकी खेती करने का फैसला लिया, और काम शुरू कर दिया.

5 एकड़ जमीन पर की खेती, चमक गयी किस्मत

राजीव ने अमरूद की खेती के लिए सबसे पहले 5 एकड़ जमीन किराए पर ली. उन्होंने इसकी खेती हरियाणा के पंचकुला में की. उन्होंने अमरूद की थाई किस्म की खेती की और उसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी. जिसके बाद राजीव के उगाए थाई किस्म के अमरूदों ने पूरे हरियाणा में तहलका मचा दिया और इसकी डिमांड बढ़ गयी. जिसके चलते सिर्फ पांच सालों में ही राजीव करोड़पति बन गये. लेकिन इन पांच सालों में उनकी खेती का रकबा बढ़ा और आज वो 5 नहीं बल्कि 25 एकड़ की जमीन में थाई किस्म के अमरूद की खेती कर रहे हैं.

अच्छी पैदावार के लिए जैविक खेती जरूरी

राजीव भास्कर की उम्र महज 30 साल ही है. उनकी मानें तो अब तक उनके खेत में लगभग 12 हजार अमरूद के पेड़ हैं. जिसके चलते वो एक साल में करीब एक से डेढ़ करोड़ तक की कमाई कर रहे हैं. राजीव बताते हैं कि, नौकरी छोड़ने के बाद जब उन्होंने पहली बार खेती करनी शुरू की थी तो, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि, ज्यादा विकास और ज्यादा उत्पादन के लिए अच्छे उर्वरक और सिंचाई की जरूरत होती है.

राजीव भास्कर अपने उगाए हुए अमरूद की खेती के बारे में बताते हुए कहते हैं कि, उनके अमरूद ना सिर्फ टेस्टी बल्कि हेल्दी और पौष्टिक तत्वों से भरपूर हैं. इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि, अगर आप जमीन पर खेती कर रहे हैं, और उर्वरकों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जगह पर जैविक खेती करने से अच्छी पैदावार मिल सकती है.

राजीव कहते हैं कि, वो अपना सारा सामान दिल्ली एपीएमसी मार्केट तक पहुंचाते है. जहां उन्हें एक हफ्ते की पेमेंट दी जाती है. अच्छी वैरायटी और मौसम के हिसाब से उन्हें प्रति किलो अमरूद के 40 से 100 रुपये के बीच तक होती है. जिस तरह वो सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपये तक कमाते हैं.

यह मौसम है सबसे अच्छा

आसान है दलहनी फसल उड़द की खेती करना

आसान है दलहनी फसल उड़द की खेती करना, यह मौसम है सबसे अच्छा

उड़द की खेती दलहनी फसल एक रूप में देश के कई हिस्सों में की जाती है. जिसमें यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं. उड़द की फसल अल्प अवधि की फसल होती है. जो दो से ढ़ाई महीने में पककर तैयार हो जाती है. उड़द के दानों में 60 फीसद कर्बोहाईड्रेट, 25 फीसद प्रोटीन और करीब 1.3 फीसद फैट होता है. अगर किसान उड़द की खेती करना चाहते हैं, तो पहले इससे जुड़ी जानकारी के बारे में जान लेना जरूरी है.

विश्व स्तर पर उड़द की खेती उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है. पिछले कई दशकों में उड़द की खेती जायद सीजन में की जा रही है. दलहनी फसल उड़द स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी होने के साथ साथ जमीन के लिए भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसके अलावा उड़द की फसल को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

उड़द की खेती के लिए कैसी हो जलवायु?

उड़द की खेती के लिए हलके नम और गर्म मौसम की जरूरत होती है. हालांकि की उड़द की फसल की ज्यादातर किस्में काफी संवेदी होती हैं. इसकी फसल को बढ़ने के लिए लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान की जरूरत होती है. लेकिन इअकी फसल 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान भी आसानी से सह सकती है. उड़द को आसानी से उगाने के लिए बारिश वाली जगहें भी उपयुक्त होती हैं. खासकर वहां जहां पर 600 से 700 मिमी बारिश हो. ज्यादा जल भराव वाली जगहों पर इसकी खेती नहीं की जा सकती. फसल में जब फूल हों या वो पकने की अवस्था में हो, तो बारिश इस फसल को बर्बाद कर सकती है.

कैसे करें भूमि का चयन?

उड़द की खेती कई तरह की जमीन में की जा सकती है. जिसमें से हल्की रेतेली, दोमट या फिर मीडियम तरह की जमीन जिसमें, पानी का निकास अच्छी तरह से हो, ऐसी जमीन उपयुक्त रहती है. उड़द की उपजाऊ जमीन के लिए उसका पी एच मां 7 से 8 के बीच का होना चाहिए. बारिश के शुरू होने से पहले ही इसके पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है. खेत समतल हो और पानी का निकास अच्छा हो, इसका ध्यान भी देना बेहद जरूरी है.

उड़द की खेती दलहनी फसल एक रूप में देश के कई हिस्सों में की जाती है. जिसमें यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं. उड़द की फसल अल्प अवधि की फसल होती है. जो दो से ढ़ाई महीने में पककर तैयार हो जाती है. उड़द के दानों में 60 फीसद कर्बोहाईड्रेट, 25 फीसद प्रोटीन और करीब 1.3 फीसद फैट होता है. अगर किसान उड़द की खेती करना चाहते हैं, तो पहले इससे जुड़ी जानकारी के बारे में जान लेना जरूरी है.

विश्व स्तर पर उड़द की खेती उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है. पिछले कई दशकों में उड़द की खेती जायद सीजन में की जा रही है. दलहनी फसल उड़द स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी होने के साथ साथ जमीन के लिए भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसके अलावा उड़द की फसल को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

उड़द की उन्नत किस्मों के बारे में

- टी-9 उड़द की किस्म को पकने में करीब 70 से 75 दिनों का समय लगता है. इसकी औसत पैदावार की बात करें तो 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी पैदावार होती है. इसका बीज मीडियम छोटा, हल्का काला और मीडियम ऊंचाई वाला पौधा होता है.
- पंत यू-30 उड़द की किस्म को पकने में 70 दिनों का समय लगता है. वहीं इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसके दाने काले और मीडियम आकार के होते हैं. जो पीला मौजेक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है.
- खरगोन-3 उड़द की किस्म को पकने में 85 से 90 दिनों का समय लगता है. इसकी औसत पैदावार 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसका दाना बड़ा और हल्का काला होता है. इसका पौधा फैलने वाला होता है.
- पी डी यू-1 उड़द की किस्म को पकने में 70 से 80 दिनों का समय लगता है. इसकी औसत पैदावार 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसका दाना काला बड़ा और जायद के सीजन के लिए बेहतर होता है.
- जवाहर उड़द-2 किस्म की उड़द की फसल को पकने में 70 दिनों का समय लगता है. इसकी पैदावार 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसके बीज मीडियम छोटे चमकीले काले, तनी पर फलियां आस पास के गुच्छों में लगती है.
- जवाहर उड़द-3 उड़द की किस्म को पकने में 70 से 75 दिनों का समय लगता है. इसके पैदावार अन्य की तुलना में कम यानि की 4 से 4.80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसके बीज मीडियम छोटे और इसका पौधा कम फैलने वाला होता है.
- टी पी यू-4 उड़द की किस्म 70 से 75 दिनों में पककर तैयार होती है. इसकी पैदावार भी 4 से 4.80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है. इसका पौधा मीडियम ऊंचाई वाला सीधा होता है.

फसल में कैसी हो खाद और उर्वरक?

उड़द की फसल दलहनी फसल होती है. जिसे ज्यादा नत्रजन की जरूरत नहीं होती. पौधों की शुरूआती अवस्था में जब तक जड़ों में नत्रजन एकत्र करने वाले जीवाणु काम करते रहते हैं, तब तक के लिए 15 से 20 किलो नत्रजन 40 से 50 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजों की बुवाई के कते समय मिट्टी में मिला दें. पूरी खाद की मात्रा बुवाई के समय कतारों में बीज के नीचे डालें.

उड़द के बीज को प्रति एकड़ के हिसाब से 6 से 8 किलो की मात्रा में बोना चाहिए. बुवाई के पहले बीज के तीन ग्राम थायरम या ढ़ाई ग्राम डायथेन एम-45 से उपचारित कर लें. इसके अलावा बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक को तकरीबन 5 से 6 ग्राम प्रति किलो की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या है बुवाई का सही तरीका?

बारिश के मौसमे के आने पर या जून के आखिरी हफ्ते में भरपूर बारिश होने पर उड़द के बीजों की बुवाई करें. इसकी बुवाई तिफन या फिर नाली में कर सकते हैं. जहां कतारों की दूरी करीब 30 सेंटी मीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 सेंटी मीटर की होनी चाहिए. बीज को 4 से 6 सेंटी मीटर की गहराई पर बोएं. गर्मियों के सीजन में इसकी बुवाई फरवरी के आखिरी तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में कर लेनी चाहिए.

कैसे करें सिंचाई?

उड़द की खेती में आमतौर पर बारिश के मौसम में सिचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन इसकी फली बनते वक्त अगर खेत में भरपूर नमी नहीं है तो एक सिंचाई जरुर कर देनी चाहिए. जायद के सीजन में उड़द की खेती के लिए तीन से चार सिंचाई की जरूरत होती है. जिसके लिए पलेवा करने के बाद बीजों की बुवाई की जाती है. जहां दो से तीन सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतर में करनी चाहिए. फसल में जब फूल बनें तो खेत में पर्याप्त नमी हो इसका ध्यान जरुर रखें.

कैसे करें रोग की रोकथाम?

- उड़द में लगने वाला समान्य रोग पीला मोजेक विषाणु रोग है. जो वायरस से फैलता है. इसका असर 4 से 5 हफ्ते के बाद नजर आता है. इस रोग में पत्तियों का रंग पीला और धब्बेदार हो जाता है. जिसके बाद पत्तियां सूख जाती हैं. इसका उपचार करके इस पर नियंत्रण किया जा सकता है.
- पत्ती मोडन रोग में पत्तियां शिराओं से ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और नीचे से अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं. जिसकी वजह से पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है और पौधे मर जाते हैं. यह एक विषाणु जनित बीमारी है. इससे बचने के लिए थ्रीप्स के लिए एसीफेट 75 फीसद एस पी या 2 मीली डाईमैथोएट प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे बुवाई करते समय ही कर देना चाहिए.
- फसल को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए कार्बेन्डाजिम 1 किलो एक हजार लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए.
- फसक को सेफ मक्खी रोग से बचाने के डायमेथोएट 30 ई सी 2 मिली लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करना चाहिए.

कैसे करें रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल?

- जब भी कीटनाशी घोल तैयार करें तो उसमें चिपचिपा पदार्थ जरूर मिलाएं. ताकि बारिश का पानी कीटनाशक पत्तियों पर पड़कर घुलकर ना बहे.
- धूल कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सुबह ही करें.
- किसी की भी सलाह पर दो या उससे ज्यादा कीटनाशकों को ना मिलाएं. मौसम के हिसाब से ही हमेशा कीटनाशकों का इस्तेमाल करें.
- जब भी कीटनाशक का घोल तैयार करें तो उसके लिए किसी मग्घे का इस्तेमाल करें. फिर स्प्रे टंकी में पानी से मिलाएं. ध्यान रखें कि, कीटनाशक को कभी भी डायरेक्ट टंकी में ना मिलाएं.

कैसे करें निदाई और गुड़ाई?

खरपतवार फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर फसल की निदाई और गुड़ाई करनी चाहिए. इसके लिए कुल्पा और डोरा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके आलवा फसलों में आधुनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए.

कैसे करें उड़द की कटाई?

उड़द की फसल लगभग 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. उड़द की फसल की कटाई के लिए हंसिया का इस्तेमाल करें. कटाई का काम कम से कम 70 से 80 फीसद फलियों के पक जाने पर करें. खलियान में ले जाने के लिए फसलों का बंडल बना लेंगे तो काम आसान हो जाएगा.
उड़द की अच्छी पैदावार के लिए आपको हमारी बताई हुई खास बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करनी चाहिए. जिससे आपको फायदा भी हो सके और अच्छी इनकम भी हो सके.

MERIKHETI